



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

190-2015/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2015 (KARTIKA 14, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 नवम्बर, 2015

संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/डी.डी.पी.(एम.बी.आई.आर.)/2015/3070.—पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा राजपत्र दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.) /डी.डी.पी. (बावल)/2007/4244, दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 तथा इसके निमित्त जारी सभी अन्य अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुबन्ध ख में विनिर्दिष्ट नियन्त्रित क्षेत्रों को लागू किए जाने वाले प्रस्तावित अनुबन्ध क तथा ख में दिये गये निर्बन्धनों तथा शर्तों सहित प्रारूप विकास योजना मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र (एम.बी.आई.आर.)-2039 प्रकाशित करते हैं।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् सरकार, प्रारूप विकास योजना पर, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, एस.सी.ओ. 71-75, द्वितीय मंजिल, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से इस योजना के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार करेगी।

ड्राईंग

1. बावल की नगरपालिका सीमा के चारों ओर नियन्त्रित क्षेत्र संख्या I, II तथा III तथा रेवाड़ी की नगरपालिका सीमा के चारों ओर अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र संख्या II के लिए तैयार की गई विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (आर.ई.) 490/2007, दिनांक 27 अगस्त, 2007 (हरियाणा राजपत्र में दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 को प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी. (एन.सी.आर.)/डी.डी.पी. (बावल)/2007/4244, दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 द्वारा पहले से ही अधिसूचित)
2. नगरपालिका नगर, रेवाड़ी के चारों ओर नियन्त्रित क्षेत्र संख्या II तथा प्राथमिक विद्यालय, गांव खलियावास के चारों ओर नियन्त्रित क्षेत्र के लिए तैयार की गई विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राईंग संख्या डी.टी.पी.(आर.ई.) 638/2013, दिनांक 24.12.2013/04.11.2015.

3. नगरपालिका नगर, बावल के चारों ओर अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र IV के लिए तैयार की गई विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राइंग संख्या डी.टी.पी. (आर.ई.) 635/2013, दिनांक 16.12.2013/19.8.2014/04.11.2015.
4. नगरपालिका, नगर, रेवाड़ी के चारों ओर नियंत्रित क्षेत्र III के लिए तैयार की गई पार्ट विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राइंग संख्या डी.टी.पी. (आर.ई.) 659/2014, दिनांक 20.11.2014/04.11.2015.
5. नगरपालिका नगर, बावल के चारों ओर नियंत्रित क्षेत्र V के लिए तैयार की गई विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राइंग संख्या डी.टी.पी. (आर.ई.) 636/2013, दिनांक 16.12.2013/19.8.2014/04.11.2015.
6. नगरपालिका नगर, धारुहेड़ा के चारों ओर नियंत्रित क्षेत्र II के लिए तैयार की गई विद्यमान भूमि उपयोग योजना ड्राइंग संख्या डी.टी.पी. (आर.ई.) 637/2013, दिनांक 16.12.2013/19.8.2013/04.11.2015.
7. प्रारूप विकास योजना मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र-2039 ई0 ड्राइंग संख्या डी.टी.पी. (आर.ई.) 632/2013, दिनांक 22 अक्टूबर, 2013/04.11.2015.

अनुबन्ध 'क'

मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र (एम.बी.आई.आर.) जिला रेवाड़ी के नियन्त्रित क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना 2039 ई0 का व्याख्यात्मक टिप्पण

परिचय:

दिल्ली तथा मुम्बई के बीच दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर (डी.एम.आई.सी.) के नाम से पश्चिमी समर्पित माल भाड़ा कोरिडोर (डी.एफ.सी.) के संरेखण के साथ-साथ 150 किलोमीटर का पट्टा विस्तारित औद्योगिक कोरिडोर विकसित करने के लिए भारत सरकार (जी.ओ.आई.) की दृष्टि है। यह उच्च गुण भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना सहित औद्योगिक विकास को उन्नत करने पर विचार करता है। डी.एम.आई.सी. विकास निगम लिमिटेड (डी.एम.आई.सी.डी.सी., विशेष प्रयोजन वाहन) ने डी.एम.आई.सी. क्षेत्र को योजनाबद्ध तथा समन्वित करने के लिए वाणिज्य मन्त्रालय (एम.ओ.सी.ओ.एम.), के अधीन सृजित किया है।

हरियाणा सरकार द्वारा सम्पूर्ण रूप से स्वामित्वाधीन हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अव-संरचना विकास निगम (एच.एस.आई.आई.डी.सी.), सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी, हरियाणा राज्य के लिए डी.एम.आई.सी., एम.बी.आई.आर. परियोजना के लिए नोडल अभिकरण है।

जुरोंग मार्गदर्शन संघ (सलाहकार) को डी.एम.आई.सी. के हरियाणा उप क्षेत्र के मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र (एम.बी.आई.आर.) के लिए विकास योजना (डी.पी.) को तैयारी हेतु सलाहकार सेवाओं की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र (एम.बी.आई.आर.) को हरियाणा के जिला रिवाड़ी में अवस्थित किए जाने वाले एक मुख्य नए औद्योगिक हब के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

एम.बी.आई.आर. प्रस्तावित माल-भाड़ा कोरिडोर (डी.एफ.सी.) रेलवे लाइन के साथ-साथ विकास के रेखीय जोन के सृजन का सूत्रपात प्रस्तावित दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना (डी.एम.आई.सी.) के अधीन निर्दिष्ट किया जाने वाला पहला निवेश क्षेत्र है।

अवस्थिति तथा संयोजन:

चिह्नित एम.बी.आई.आर. हरियाणा के जिला रिवाड़ी के भीतर अवस्थित है। यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) के दक्षिण-पश्चिमी दिशा में 82 किलोमीटर मील पथर पर अवस्थित है। जिले की भौगोलिक स्थिति 27° 57' एन से 28° 27' एन अक्षांश तथा 76° 17' ई0 से 76° 51' ई0 देशान्तर है। इसकी भौगोलिक सीमाएं इसके उत्तर में जिला झज्जर, इसके पश्चिम में जिला महेन्द्रगढ़ तथा इसके पूर्व तथा उत्तर-पूर्व दिशा में जिला गुडगांव है। राजस्थान का जिला अलवर दक्षिण-पूर्व में रेवाड़ी को छूता है। रिवाड़ी जिला हरियाणा, के एन.सी.आर., पंजाब, राजस्थान तथा शेष भारत भीतर सभी मुख्य कटान बिन्दु के राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों तथा रेलों के नेटवर्क से भली भान्ति जुड़ा हुआ है। सड़कों की कुल लम्बाई 860 किलोमीटर है तथा सभी गांव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं। रिवाड़ी जिला भारत का उच्च सघनता रेलवे नेटवर्क जिलों में से है। रिवाड़ी रेलवे स्टेशन (जंक्शन) छह रेलवे लाइनों अर्थात् (क) दिल्ली-रिवाड़ी-अलवर-जयपुर/मथुरा, (ख) दिल्ली-रिवाड़ी-नारनौल-जयपुर, (ग) रिवाड़ी-महेन्द्रगढ़-लौहारू-बिकानेर, (घ) रिवाड़ी-भिवानी-हिसार तथा (ड.) रिवाड़ी-झज्जर-रोहतक लाइनों को मिलाने वाला संगम बिन्दु है।

रिवाड़ी जिले में से गुजरने वाला समर्पित माल भाड़ा कोरिडोर (डी.एफ.सी.) का हरित क्षेत्र संरेखण सभी वर्तमान तथा निर्माणाधीन रेलवे संयोजनों से जुड़ा हुआ है। डी.एफ.सी. जंक्शन स्टेशन मेगा संचार-तंत्र पार्क के साथ-साथ रिवाड़ी शहर के निकट विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली रिवाड़ी शहर से 80 किलोमीटर दूर है तथा जयपुर हवाई अड्डा 209 किलोमीटर की दूरी पर है।

जलवायु:

सामान्य तौर पर रिवाड़ी में 'तेज धूप तथा वर्षा का अभाव तथा परिवर्तनशीलता' है तथा वाष्पीकरण की उच्चतर मुख्य जलवायु घटक हैं। रिवाड़ी जिले की जलवायु को उष्णकटिबन्धी घास का मैदान; अर्ध-सूखा तथा गर्म अर्थात् बहुत गर्मी सहित

मुख्य रूप से शुष्क तथा सर्दियों में ठण्डे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें मानसून अवधि शामिल नहीं है जब जिले में समुद्री उद्गम प्रवेश से नम वायु होती है।

(क) **तापमान:** जलवायु गर्मी तथा सर्दी में तापमान के नितान्त सहित गर्म तथा अर्ध-सूखा है। क्षेत्र में क्रमशः जनवरी तथा मई/जून के दौरान 5.6° सैल्सियस से 41° सैल्सियस तक की रेंज में न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान रहता है।

(ख) **वर्षा:** जिले में सामान्य मानसून तथा वार्षिक वर्षा क्रमशः 489 मिलीमीटर तथा 553 मिलीमीटर है, जो क्षेत्र में ऊंची-नीची होती रहती है।

सम्बन्धित नमी: सम्बन्धित नमी अप्रैल से जून तक के महीने के दौरान 30 प्रतिशत से कम है तथा मानसून के महीने में 70 प्रतिशत से अधिक है।

वायु दिशा: रिवाड़ी के लिए आई.एम.डी. डाटा सूचित करता है कि कुल प्रमुख वायु दिशा गर्मी के मौसम के दौरान पश्चिम (54 प्रतिशत) से है। तथापि, वार्षिक पद्धति दर्शाती है कि प्रमुख संयुक्त वायु दिशा पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम से है।

भूविज्ञान तथा प्राकृतिक संयोग:

रिवाड़ी जिले के अश्म-विज्ञान को दो बृहत भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात् (क) सख्त चट्टान, (ख) एईओलियन तथा नदीय उद्गम दोनों का असमेकित तलछट।

(क) **आकृति तथा ढाल:** सामान्यतः जिले में अधिकतम आकृति अवशिष्ट संरचनात्मक पहाड़ियों पर अवलोकित किया गया है जहां सामान्य उत्थापन समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर है। कछारी भूमि सहित भूमि का कुल ढाल उत्तर की ओर है। राजस्थान की सीमा की ओर एम.बी.आई.आर. की दक्षिण-पश्चिमी तरफ कुछ पथरीली दृश्यांश दिखाई देता है जो लगभग उंचाई में 300 मीटर हैं। साहिबी नदी एम.बी.आई.आर. के उत्तरी भाग में बहती है।

(ख) **भू-जल:** जिले में भू-जल असीमित, अर्ध सीमित तथा सीमित स्थिति में होता है तथा क्रमशः खोदे हुए कुओं, छिछले नलकूपों तथा गहरे नलकूपों द्वारा उपयोग किया जाता है। एम.बी.आई.आर. के अधिकांश भाग में भू-जल का दरजा एन.एच-48 पर पार्श्व नमकीन के छोटे टुकड़ों सहित उप पार्श्व नमकीन है। इसके अतिरिक्त ताजा पानी एम.बी.आई.आर. के दक्षिणी और पर साहिबी नदी के साथ पाया जाता है। रिवाड़ी जिले का शुद्ध भूजल स्रोत 260.65 करोड़ घन मीटर (एम.सी.एम.) के रूप में अनुमानित है तथा जिले का ठोस भूजल खाका (-) 54.68 एम.सी.एम. की कमी को पीछे छोड़कर 313.91 एम.सी.एम. है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने भूजल विकास के नियमन के लिए खोल खण्ड अधिसूचित किया है।

(ग) **मिट्टी गुण:** जिला भारत-गैन्नीटीक मैदान का भाग रूप है। जिले की मिट्टी की बनावट रेतीली से दुम्मी रेत में परिवर्तित करती है। जिला दुम्मी रेत बनावट के अधीन लगभग 90 प्रतिशत मिट्टी है। मोटी बनावट होने के कारण मिट्टी जल में तथा पोषक धारण में कमजोर है।

वन तथा प्राकृतिक विशेषता:

रिवाड़ी जिला तथा परिणामस्वरूप एम.बी.आई.आर, जैव-भौगोलिक प्रदेश के निबन्धनों के अनुसार अर्ध-शुष्क पंजाब मैदान में आता है। जिले में अधिकांश वन उप-उष्णकटिबन्धी कंटीले वन से सम्बन्धित है। जिले में वृक्ष प्राकृतिक वन क्षेत्रों की बजाए गैर-वन क्षेत्र में अधिक है। भारत के वन सर्वे की राज्य वन रिपोर्ट, 2005 के अनुसार कुल जैव भौगोलिक क्षेत्र का 2.64 प्रतिशत कुल वन आकृत क्षेत्र है।

तीन मुख्य प्राकृतिक विशेषताएं चित्रित क्षेत्र में पहचान की गई थी। ये (i) साहिबी नदी (ii) अरावली पहाड़ी तथा (iii) वन क्षेत्र। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में विभिन्न (कीकर) सघन पौधारोपण अवलोकित किया गया था। अरावली पहाड़ियों के अधीन क्षेत्र लगभग 13.5 वर्ग किलोमीटर है जबकि वन क्षेत्र केवल 1.4 वर्ग किलोमीटर में है। तथापि कीकरों वाला क्षेत्र काफी है जो 17.74 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार, 32.68 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्र प्राकृतिक विशेषताओं के अधीन है (जिसमें साहिबी नदी शामिल है)।

समर्पित मालभाड़ा कोरिडोर:

भारत सरकार ने 1483 किलोमीटर की कुल लम्बाई को मिलाकर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में तथा मुम्बई के निकट जवाहर लाल नेहरू बन्दरगाह के अन्तिम सिरे सहित यूपी., एन.सी.टी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र के राज्यों से गुजरते हुए दिल्ली तथा मुम्बई (डी.एफ.सी. पश्चिमी) के बीच डी.एफ.सी. की स्थापना करने की घोषणा की है। यह डी.एफ.सी. उच्च शक्ति इंजन द्वारा समर्थित दुगना राशीकृत कन्टेनर ट्रेन की उच्च एक्सल आर वैगन (25 टन) के लिए उच्च-गति से सम्बन्धित है। पश्चिमी डी.एफ.सी, 2016-17 में परिचालन होना सम्भावित है।

विकास योजना व्यवस्था:

एम.बी.आई.आर., का चित्रित स्थल की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 2,20,048 की संयुक्त वर्तमान जनसंख्या सहित 140 गांवों मिलाते हुए तथा 402.20 वर्ग किलोमीटर को बांटते हुए वर्तमान बावल औद्योगिक क्षेत्र तथा बावल करबे का बृहत विस्तार करता है।

योजना का प्रावस्था रीति में 2039 तक औद्योगिक तथा जनसंख्या वृद्धि को समायोजित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। यह 33.15 लाख लोगों को समायोजित करने के लिए रिहायशी क्षेत्र के साथ-साथ बृहत संसक्त औद्योगिक क्षेत्र मुहैया करता है। यह अनुमानित है कि लगभग 736666 निवास इकाई 4.5 व्यक्तियों के औसत परिवार आकार पर आधारित होना अपेक्षित होगा। अतः 4.5 व्यक्तियों के औसत परिवार अनुसार आकार पर आधारित कुल आबादी 33.15 लाख होगी।

भूमि उपयोग वितरण:

योजना औद्योगिक गतिविधियों, रोजगार तथा आधुनिक शहर को जारी रखने के लिए आवश्यक आवासीय, वाणिज्यिक तथा अन्य भूमि उपयोगों सहित जनसंख्या आधार के लिए प्रक्षेपित भूमि मांग समायोजित करने के लिए निर्दिष्ट की गई है।

9 नियन्त्रित क्षेत्रों को शामिल करते हुए विकास योजना का कुल क्षेत्र लगभग 40220 हैक्टेयर है। विस्तृत प्रवर्गों के अधीन इस क्षेत्र का विघटन निम्न अनुसार है :-

क्रम संख्या	प्रवर्ग	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	प्रस्तावित शहरीयोग्य क्षेत्र	26737
2.	कृषि जोन	7935
3.	विद्यमान व्यवस्था	1654
4.	विद्यमान औद्योगिक सम्पदा	1081
5.	प्राकृतिक संरक्षण जोन	2813
	कुल	40220

शहरीकरण योग्य जोन को विभिन्न भूमि उपयोगों में विभाजित किया गया है; जिसका विवरण इस प्रकार है:

भाहरीयोग्य जोन के भूमि उपयोगों का क्षेत्र विवरण

क्रम संख्या	भूमि उपयोग	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	प्रतिशत
1.	आवासीय	9724	36.37
2.	वाणिज्यिक	1149	4.30
3.	औद्योगिक	5247	19.62
4.	परिवहन तथा संचार	4266	15.96
5.	जन उपयोगिताएं	396	1.48
6.	सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक	944	3.53
7.	खुले स्थान	5011	18.74
	कुल	26737	100

(क) आवासीय उपयोग :

9724 हैक्टेयर का क्षेत्र 341 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर की औसत आवासीय घनत्व के साथ 33.15 लाख प्रक्षेपित जनसंख्या को समायोजित करने के आवासीय प्रयोजन के लिए चिन्हित किया गया है। यह प्रस्तावित है कि पूर्वोक्त आवासीय क्षेत्र सार्वजनिक तथा निजी सैक्टरों द्वारा अर्थात् पी.पी.पी. ढंग पर विकसित किए जाएं। आवासीय क्षेत्र सैक्टर घनत्व के अनुसार सैक्टरों में सभी सामुदायिक सुविधाएं तथा सेवाओं की व्यवस्था करते हुए परिवेशी धारणा पर विकसित किए जाने प्रस्तावित है। घनत्व पट्टी इसके उच्चतर समापन पर 100 आवास इकाई से अधिक निम्नतम समाप्ति पर 30 आवास इकाईयों से कम रेंज तक अपनाई गई है। आवासीय घनत्व के तीन प्रवर्ग प्रस्तावित किए गए हैं— (क) निम्न घनत्व—150 पी.पी.एच. (ख) मध्यम घनत्व—300 पी.पी.एच.ए. तथा (ग) उच्च घनत्व—450 पी.पी.एच.ए. आवासीय भूमि उपयोग वितरण अपनाई गई आश्रय जीवन, शहरी जीवन तथा परिवर्तित जीवन की विषयक धारणा द्वारा संचालित है। केन्द्रीय कारोबार जिला (सी.बी.डी.) अर्थात् क्षेत्रीय केन्द्र उच्च घनत्व आवासीय विकास के शहरी जीवन संघरित करने के भाग के रूप में है। मध्यम घनत्व आवासीय क्षेत्र निवेश क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम भाग की ओर एस.एच. 15 तथा वी-2 के बीच पट्टी के साथ सकेंद्रित हैं। निम्न घनत्व आवासीय क्षेत्र मानेसर बावल के साथ-साथ उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उच्च रूप से सकेंद्रित है। यह आवासीय क्षेत्र विकास जैसे कि बंगले, तटस्थ तथा अर्ध-तटस्थ आवास सहित आश्रय जीवन की धारणा पर विकसित किया जाएगा। निम्न घनत्व आवासीय क्षेत्र का दूसरा भूमि खण्ड अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं के समर्थन से निवेश क्षेत्र के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। सैक्टर के निर्वाह पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न अनुसार प्रस्तावनाएं प्लान में की गई हैं:-

- (क) योजना में 10 टाउन पार्क होंगे जिनका प्रत्येक का एरिया 4 हेक्टेयर होगा जो कि प्लान में पूर्णतया व्यवस्थित होंगे।
- (ख) रिहायशी कालोनी/ सैक्टर में पार्क/खुले स्थानों के लिए न्यूनतम क्षेत्र ऐसी रीति में आयोजित किये जाएंगे जो 2.5 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति के न्यूनतम मानक को पूरा करेगा।
- (ग) रिहायशी कालोनी/ सैक्टर में दी जाने वाली सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर से कम नहीं होगी।

(ख) वाणिज्यिक उपयोग:

1149 हेक्टेयर का क्षेत्र वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। निवेश क्षेत्र के सफल कृत्य सुनिश्चित करने तथा 2039 ई0 तक 33.15 लाख की प्रक्षपित जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक केन्द्रों का श्रेणीबद्ध संगठन पड़ोसी केन्द्र के लिए केन्द्रीय कारबार जिला, क्षेत्रीय केन्द्र, शहर केन्द्र तक रेंज के लिए प्रस्तावित योजना में मुहैया कराए गए हैं। सी.बी.डी. वाणिज्यिक सैक्टर सी-13 से सी-16, वाणिज्यिक सैक्टर में क्षेत्रीय केन्द्र सैक्टर सी-1, से सी-6, सैक्टर सी-20 से सी-23 में उप-क्षेत्रीय केन्द्र में अवस्थित होंगे जबकि शहर/पड़ोस केन्द्र व्यक्तिगत सैक्टरों की अभिन्यास योजनाओं की तैयारी करने के बाद अवस्थित किया जाएगा।

वाणिज्यिक/वित्तीय गतिवधि का मुख्य फोकस सी.बी.डी. तथा दो क्षेत्रीय केन्द्रों में सकेन्द्रित किया जाएगा। सी.बी.डी. को एन.एच.-48 के साथ दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में विश्व श्रेणी कारोबार जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्देश्य आर्थिक विकास सृजित करना है जो सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र के लिए नई सरहद के रूप में सेवा करेगा।

एन.एच.-48 के साथ-साथ उत्तर-पूर्व भाग में क्षेत्रीय केन्द्र मुख्य वाणिज्यिक/संस्थागत हब होगा। जबकि एस.एच.-15 के साथ-साथ क्षेत्रीय केन्द्र अधिक खुदरा लक्ष्य तथा मनोरंजन उपयोगों की ओर अधिक प्रबन्ध करेगा।

(ग) औद्योगिक उपयोग:

औद्योगिक सैक्टर 2039 ई. तक उद्योगों के विकास के लिए लगभग 1.6 करोड़ के लिए रोजगार सृजित करना समीपवर्ती है तथा विद्यमान औद्योगिक सम्पदा से अलग अतिरिक्त 5247 हेक्टेयर अपेक्षित है। मोटे तौर पर लम्बी अवधि योजना तथा प्रक्षेपण प्रयोजनों के लिए औद्योगिक भूमि हेतु मांग को निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है: कारबार पार्क, मानक/फलैटिड कारखाने, आबंटित लाट्स, विशेष उद्योग।

प्रस्तावित औद्योगिक भूमि की अवस्थिति माल का उचित संचलन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित संभार-तन्त्र हब सहित विद्यमान बावल औद्योगिक सम्पदा के साथ लगते सैक्टरों में दी गई है। आयोजना पर्यावरणात्मक संघटन तथा निकटवर्ती व्यवस्थाओं पर विचार करती है। कुल 300 मीटर हरित बफर सहित 80 मीटर चौड़ी सड़क आवासीय सैक्टर से औद्योगिक क्षेत्र को पृथक करता है। स्वच्छ/हरित उद्योग तथा कारबार पार्क विकास की तरह जीवन-कार्य अभिनय करने के लिए नए नगर क्षेत्र के भीतर अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा उद्योगों के गन्दे पानी की निकासी के लिए तथा औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमिगत जल की निकासी अनुमत नहीं होगी।

(घ) परिवहन तथा संचार:

विकास योजना लोक तथा निजी परिवहन दोनों को शामिल करने वाली बहु-रूपात्मक परिवहन युद्ध-नीति पर आधारित है। सड़कों, पटरी तथा साइकिल-पथ की एक अच्छी प्रणाली तथा लोक परिवहन प्रणाली परिवहन मांग का मेल मिलाने के लिए विकसित की जानी प्रस्तावित हैं। 4266 हेक्टेयर का क्षेत्र सड़कों, आई.एस.बी.टी, बस डिपो/केन्द्र, हेलीपैड, रेल लाइन, डी.एफ.सी. तथा संभार-तन्त्र सुविधाएं जैसे कि संघटित बहु रूपात्मक संभार-तन्त्र हब, भाण्डागार कृषि मण्डी इत्यादि के लिए मुहैया कराने हेतु परिवहन संचार के लिए एकीकृत किया गया है।

सड़क नेटवर्क रिवाड़ी, धारुहेड़ा तथा बावल विकास योजना तथा ग्रिड नेटवर्क की धारणा के वर्तमान तथा योजनाबद्ध सड़क नेटवर्क के माध्यम से इसका रूप व्युत्पन्न करता है। योजना का खाका शहरी सड़क (मुख्य, उप-मुख्य तथा कलक्टर सड़क) जमा क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय महत्वता (एन.एच तथा एस.एच.) की सड़कों के झुण्ड के नेटवर्क सहित है जिसकी चौड़ाई तथा आर.ओ.डब्ल्यू को मानकीकृत किया गया है।

एम.बी.आई.आर. के भीतर शहरी सड़कों की कुल लम्बाई लगभग 547 किलोमीटर है; जिसमें एन.एच./एस.एच./बाहरी रिंग सड़क शामिल हैं। एम.बी.आई.आर. सड़क नेटवर्क के लिए मुख्य विकास योजना सड़कों तथा लेन आकृति हेतु भूमि आरक्षण निम्न अनुसार है:-

विकास योजना सड़कों के लिए भूमि आरक्षण

क्रम संख्या	वर्गीकरण	भूमि आरक्षण	टिप्पणी
मुख्य सड़क			
I	वी.एन.-1	दोनों ओर पर 60 मीटर हरित पट्टी सहित 60 मीटर चौड़ाई	राष्ट्रीय राजमार्ग-48

II	वी.एन.-2	दोनों ओर पर 50 मीटर हरित पट्टी सहित वर्तमान चौड़ाई	राष्ट्रीय राजमार्ग-71
III	वी.एस.	दोनों ओर पर 30 मीटर हरित पट्टी सहित 60 मीटर चौड़ाई	राज्य राजमार्ग
IV	वी.बी.	दोनों ओर पर 100 मीटर हरित पट्टी सहित 100 मीटर चौड़ाई	बी.आर.टी. वाला सम्पूर्ण रुट बावल परिधीय सड़क
V	वी.-1	दोनों ओर पर 50 मीटर हरित पट्टी सहित 80 मीटर चौड़ाई	एम.बी.आई.आर. परिधीय सड़क सहित
VI	वी.-1 (क)	दोनों ओर पर 50 मीटर हरित पट्टी सहित 80 मीटर चौड़ाई	बी.आर.टी. वाला सम्पूर्ण रुट
VII	वी.-2	दोनों ओर पर 50 मीटर हरित पट्टी सहित 60 मीटर चौड़ाई	
VIII	वी.-2 (क)	दोनों ओर पर 50 मीटर हरित पट्टी सहित 60 मीटर चौड़ाई	बी.आर.टी. वाला सम्पूर्ण रुट
IX	वी.-2 (ख)	दोनों ओर पर 30 मीटर हरित पट्टी सहित 60 मीटर चौड़ाई	बी.आर.टी. वाला सम्पूर्ण रुट
उप-मुख्य सड़क			
X	वी.-2 (ग)	60 मीटर चौड़ी	
XI	वी.-2 (घ)	60 मीटर चौड़ी	बी.आर.टी. वाला सम्पूर्ण रुट
XII	वी.-3	दोनों ओर पर 30 मीटर हरित पट्टी सहित 45 मीटर चौड़ाई	
XII	वी.-3 (क)	45 मीटर चौड़ी	

एम.बी.आई.आर. सड़क नेटवर्क के लिए लेन आकृति

क्रम संख्या	सड़क प्रवर्ग	निर्दिष्ट लेन आकृति
I	मुख्य सड़क	दोनों ओर पर सर्विस लेन, पट्टी तथा गैर-मोटराइज्ड सहित 8/6 लेन में विभक्त वाहन पथ
II	उप-मुख्य सड़क	दोनों ओर पर सर्विस लेन, पट्टी तथा गैर-मोटराइज्ड सहित 4 लेन में विभक्त वाहन पथ
III	बावल परिधीय (आन्तरिक) रिंग सड़क	दोनों ओर पर सर्विस लेन, पट्टी तथा गैर-मोटराइज्ड सहित 6 लेन में विभक्त वाहन पथ
IV	एम.बी.आई.आर. परिधीय (बाहरी) रिंग सड़क	दोनों ओर पर सर्विस लेन, पट्टी तथा गैर-मोटराइज्ड सहित 6 लेन में विभक्त वाहन पथ
V	राष्ट्रीय राजमार्ग	दोनों ओर पर सर्विस लेन, पट्टी तथा गैर-मोटराइज्ड सहित 8 लेन में विभक्त वाहन पथ
VI	राज्य राजमार्ग	दोनों ओर पर सर्विस लेन, पट्टी तथा गैर-मोटराइज्ड सहित 4 लेन में विभक्त वाहन पथ

भू-स्थिति को देखते हुए, जहां ऊपरी पुल पर गढ़ी-बोलनी चौक पर जंकशन के कोट-कासिम सड़क पर जंक्शन के समान्तर चलते हुए डी.एफ.सी तथा प्रस्तावित आई.एम.एल.एच विकसित किया जा रहा है, बावल परिधीय सड़क की सीध को ऊपरी पुल के लाभ के लिए तथा उसी समय आई.एम.एल.एच को जोड़ने के लिए बदला गया है।

अन्य सड़कों की चौड़ाई तथा सिधार्ई सैक्टर प्लान के अनुरूप अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिन्यास योजना के अनुरूप होगी। जहां कहीं विकास योजना में दिखाई गई सड़क भूमि स्थिति के अनुरूप गैर सम्भाव्य पाई जाती है, सरकार कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे पुनः बनाने / निकाल देने में सक्षम होगी।

इसी अनुसार बावल परिधीय सड़क 58 किलोमीटर लम्बी एम.बी.आई.आर. परिधीय सड़क (दोनों ओर पर 50 मीटर हरित पट्टी सहित 80 मीटर चौड़ी) मुहैया कराई गई हैं जो आन्तरिक यातायात संचलन को बाधा डाले बिना मुख्य एन.एच तथा एस.एच. से यातायात को एकत्र करेगा तथा अस्तव्यस्त कर देगा।

सभी मुख्य सड़कों को विभिन्न अवस्थितियों पर ऊपरी पुलों, तिपतिया दल तथा रेलवे ऊपरी पुलों सहित बिना सिगनल की सड़क के रूप में योजनाबद्ध किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के अधीन आने वाली सभी सड़कों के सिवाए निर्बाध तथा सुरक्षित पैदल गुजरने वालों के लिए पैदल ऊपरी पुल सभी सड़कों पर योजनाबद्ध किए गए हैं। लगभग 1000 पैदल ऊपरी पुल (प्रत्येक 500 मीटर) संख्या एम.बी.आई.आर के भीतर योजनाबद्ध शहरी सड़कों पर अपेक्षित होंगे। ये सभी 49 अदला-बदली विनिमय बिना सिगनल के होंगे तथा ऊपरी पुल (19), तिपतिया दल अदला-बदली (16) तथा आर.यू.बी. सहित प्रस्तावित है।

प्रक्षपित/अनुमानित चढ़ने वालों को निश्चित करने के लिए बी.आर.टी कोरिडोर, चयनित मुख्य तथा उप-मुख्य सड़कों पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। योजनाबद्ध शहरी सड़कों का लगभग 18 प्रतिशत बी.आर.टी.एस. प्रणाली वाला होगा। बी.आर.टी कोरिडोर की कुल लम्बाई लगभग 100 किलोमीटर है। 200/250 बसों के बेड़े के आकार तथा क्रमशः प्रत्येक 12 एकड़ तथा 4 एकड़ के क्षेत्र के भीतर 15 बस टर्मिनलों के लिए एक बस डिपो मुहैया कराया गया है।

- संघटित यात्री हब: यह आई.एस.बी.टी, बस डिपो तथा यात्री बस टर्मिनल तथा कर्मशाला तथा एम.आर.टी.एस, से अन्तःसम्बन्ध से मिलकर बनेगा।
- यात्री हब: यह बस डिपो तथा बस टर्मिनल से मिलकर बनेगा।
- बस टर्मिनल: यह मुख्यतया स्थानीय बस स्टेशन होगा।

विकास योजना एम.बी.आई.आर. के भीतर हैलीपोर्ट के विकास के लिए 5 हैक्टेयर भूमि मुहैया कराती है। रेल प्रणाली की चार किस्में एम.बी.आई.आर. क्षेत्र में अभिभावी की गई हैं— (क) भारतीय रेल, (ख) प्रस्तावित समर्पित माल भाड़ा कोरिडोर, (ग) प्रस्तावित गुडगांव-बावल एम.आर.टी.एस. तथा (घ) प्रस्तावित नई दिल्ली-अलवर क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली।

(ड.) जन उपयोगिताएं:

लगभग 396 हैक्टेयर का क्षेत्र जन उपयोगिताओं जैसे कि जल आपूर्ति प्रणाली, मलवहन प्रणाली, जल निकास, ठोस अपशिष्ट निपटान प्रणाली इत्यादि के लिए प्रस्तावित की गई है। जन उपयोगिताएं उनकी मांग तथा अन्तिम उपभोक्ता की निकटता के आधार पर निर्धारित की गई है। मसानी बांध के बाढ़-द्वारों आदि के साथ पूर्ण विकसित किया जायेगा और एम.बी.आई.आर. की तीन महीने के जलापूर्ति की मांग को पूरा करने के लिए इसकी क्षमता में वृद्धि कर मुख्य जल भण्डारण जलाशय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बरसात/बाढ़ के पानी की निर्वाध एवं त्वरित निकासी हेतु सड़क की चौड़ाई के अंदर सुनियोजित जल निकासी संरचना की योजना बनाई जाएगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा समूचे एम.बी.आई.आर. में 45 एम.एल.डी. से अधिक भू-जल का दोहन न करने बारे सुनिश्चित किया जाएगा। मौजूदा पेय आपूर्ति योजनाओं को जारी रखा जाएगा तथा एम.बी.आई.आर. की अपनी पानी की आपूर्ति हेतु बुनियादी ढांचा होगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक जल आपूर्ति योजना बावल औद्योगिक क्षेत्र के वर्तमान एवं विस्तार के लिए जल आपूर्ति हेतु विस्तार होगा। इसके अतिरिक्त जल भण्डारण एवं पूर्ण भारण संरचनाओं के लिए मौजूदा तालाबों का भी उपयोग किया जाएगा।

(च) सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक:

33.15 लाख जनसंख्या की शैक्षणिक मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 944 हैक्टेयर का क्षेत्र योजना में सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक उपयोगों के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके वितरण को एम.बी.आई.आर. के भीतर सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक उपयोगों की विभिन्न किस्मों के लिए अच्छे स्थान को ध्यान में लिया गया है। सार्वजनिक/अर्ध-सार्वजनिक उपयोग आवासीय क्षेत्र में संघटित करने के उद्देश्य से रखे गये हैं। उसके द्वारा यात्रा को आवश्यकता को कम किया गया है तथा इसके निवासियों के लिये जीवन का उच्चतर दर्जा सृजित किया गया है। मुख्य सार्वजनिक उपयोग नोडस सी.बी.डी. तथा क्षेत्रीय केन्द्रों में निर्धारित किए गए हैं। अन्य सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक उपयोग वाणिज्यिक केन्द्रों के निकट पड़ोस में निर्धारित किए गए हैं। मुख्य सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक हब एन.एच.-48, बी.-2 सड़क तथा अन्य मुख्य सड़कों पर निर्धारित किए गए हैं।

(छ) खुले स्थान:

5011 हैक्टेयर का क्षेत्र खुले स्थान के अधीन मुहैया कराया गया है। खुले स्थान का आवंटन तथा वितरण निम्न अनुसार है:-

1. साहीबी नदी तथा मसानी बैरेज के साथ-साथ पार्क तथा खेल सुविधाएं।
2. साहीबी नदी के साथ-2 गोल्फ कोर्स सहित मनोरंजन तथा खेल गतिविधियां।
3. शहर स्तर पर तीन बहुत बड़े क्षेत्रीय पार्क।

4. औद्योगिक तथा आवासीय उपयोग के बीच 300 (250+50) मीटर हरित पट्टी।
5. मुख्य सड़क के साथ-साथ हरित पट्टी मुहैया कराई गई हैं।
6. हरित बफर साइकिल पथ तथा पैदल पथ के लिए मुहैया कराए गए हैं।

कृषि जोन:

विस्तृत क्षेत्र राजस्थान सीमा के साथ-साथ कृषि जोन के रूप में आरक्षित किया गया है। तथापि, यह जोन इस क्षेत्र के भीतर आवश्यक भवन विकास को अलग नहीं करेगा जैसे कि वर्तमान गांवों का विस्तार किन्तु आबादी क्षेत्र से संलग्न यदि सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित परियोजना या कृषि जोन के रूप में क्षेत्र के अनुरक्षण तथा सुधार के लिए आवश्यक अन्य अनुषंगी तथा सहबद्ध सुविधाएं दी गई हैं।

प्राकृतिक संरक्षण जोन:

अरावली रेंजों को उन क्षेत्रों के सिवाए जो शहरी योग्य क्षेत्र में आते हैं, क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार योजना में प्राकृतिक संरक्षण जोन के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। 2813 हेक्टेयर कुल क्षेत्र इस जोन के लिए उद्दिष्ट किया गया है, जिसमें गतिविधियां जैसे कि; कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, सामाजिक वन, वनरोपन तथा क्षेत्रीय मनोरंजन गतिविधियां सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरणात्मक समाशोधन प्राप्त करने के बाद अनुज्ञेय होगा। प्राकृतिक संरक्षण जोन में वही गतिविधियां अनुमत होंगी जो संशोधित क्षेत्रीय योजना 2021 एडी / उप क्षेत्रीय योजना 2021 एडी में अनुमोदित है।

पर्यावरण सम्बन्ध:

अरावली के संरक्षण के लिए, एम.ओ.ई.एफ, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 7-5-1992 लागू होगी। इसी प्रकार, किसी परियोजना के निष्पादन के लिए, परियोजना प्रस्तावक दिनांक 14.9.2006 की अधिसूचना के निबन्धनों में पर्यावरण समाशोधन प्राप्त करना होगा जो सहज में ही अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, पंजाब भू-संरक्षण अधिनियम, 1900 की धारा 4 तथा/या 5 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र तथा अरावली पौधारोपण के अधीन आने वाले क्षेत्रों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए 'वन' के रूप में दर्शाया गया है जिसमें कोई भी शहरीकरण अनुज्ञात नहीं होगा। इसी प्रकार, किसी रीति में पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबन्धों का अनुपालन भी किया जाएगा तथा लागू भी किया जाएगा। समय-समय पर एम.ओ.ई.एफ, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना लागू होगी तथा बाध्य होगी।

पैतृक सम्पत्ति स्थलों का संरक्षण:

स्मारक, पैतृक सम्पत्ति, सौन्दर्यपरक के विशेष क्षेत्र, भावुक या ऐतिहासिक मूल्य जिनका संरक्षण अपेक्षित है, को संरक्षित किया जाएगा।

जोनिंग विनियमन:

भूमि के उपयोग के संबंध में प्रस्तावों को कानूनी मान्यता जोनिंग नियमों का एक सेट (अनुबंध बी) द्वारा प्रभाव को देखते हुए किया जा रहा है, जो इस विकास की योजना का हिस्सा है। इन नियमों को भूमि के उपयोग और विकास के मानकों के परिवर्तन को नियंत्रित करेंगे। उन्होंने यह भी अलंकृत विस्तार से बाहर संबद्ध होगा और विभिन्न प्रमुख भूमि उपयोग में अनुमति दी है और किया जाएगा, जिसमें सहायक का उपयोग करता है भूमि के उपयोग और विकास के सभी परिवर्तन जिसके लिए विस्तृत क्षेत्र की योजना की तैयारी सुनिश्चित सैक्टर योजना में दिखाया विवरण के अनुसार किया जाएगा कि निर्धारित प्रत्येक क्षेत्र के विकास के मार्गदर्शन और समुचित नियंत्रण लागू करने के लिए।

अनुबन्ध ख

अंचल विनियम

धारा 5 के अधीन प्रकाशित मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र की विकास योजना में आने वाले नियन्त्रित क्षेत्र में भूमि का उपयोग तथा विकास की ड्राईंग संख्या डी.टी.पी (आर.ई) 632/2013, दिनांक 22 अक्टूबर, 2013/04.11.2015 में दर्शाए गए अनुसार शासित किया जाएगा।

1. सामान्य

- (1) मानेसर बावल निवेश क्षेत्र-2039 ई. प्रारूप विकास योजना का भाग रूप बनने वाले ये अंचल विनियम प्रारूप विकास योजना मानेसर बावल निवेश क्षेत्र-2039 ई. के अंचल विनियम कहे जाएंगे।
- (2) इन विनियमों की अपेक्षाएं प्रारूप विकास योजना में आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए विस्तारित की जाएंगी तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 41) तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगे।

II परिभाषायाः

इन विनियमों में; संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित के सिवाए :-

- (i) “कृषि आधारित उद्योग” से अभिप्राय है, एक ऐसा औद्योगिक यूनिट, जो खाद्यान्न, फलों या कृषि संबंधी कचरे का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है;
- (ii) “अनुमोदित” से अभिप्राय है, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अनुमोदित;
- (iii) “भवन नियमों” से अभिप्राय हैं, नियमों के भाग—VII में निहित नियम;
- (iv) “साइबर सिटी” से अभिप्राय है, परिपूर्ण शहर जिसमें मूलभूत ढांचा अति उच्चतम गुणवत्ता का हो, सूचना प्रौद्योगिकी धारणा को एकत्र करने के लिए विकसित की जाने वाली आकर्षक प्रतिवेशी तथा उच्च गति संचार प्रणाली पहुँच तथा मध्यम तथा बड़ी साफ्टवेयर कम्पनियाँ/सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं की कम्पनियाँ अंकुरित हों जिसमें उत्पादन करने वाली ईकाइयों को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- (v) “साइबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क” से अभिप्राय है वह क्षेत्र जो अनन्य साफ्टवेयर विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप तथा सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हों, इसमें किसी भी प्रकार के उत्पादन (असम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- (vi) “ड्राईंग” से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या – डी.टी.पी.(आर.ई.) 632/2013 दिनांक 22 अक्टूबर, 2013/04.11.2015;
- (vii) “व्यापक उद्योग” से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों तथा जिसमें ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये बशर्ते कि इसमें किसी प्रकार से हानिकारक तत्व न हो;
- (viii) “फार्म गृह” से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनार्थ निर्मित घर –
 - (क) निवास यूनिट अर्थात् मुख्य उपयोग; तथा
 - (ख) फार्म छायाबान अर्थात् गौण उपयोग।

टिप्पणः

- (1) फार्म गृह का निर्माण “कृषि अंचल में आबादी देह से बाहर फार्म गृहों की व्यवस्था” संबंधी खण्ड XXI के अधीन दिये गये निर्बन्धनों द्वारा शासित होगा;
 - (2) फार्म शैड, “भवन नियंत्रण और स्थल विशिष्टियों” संबंधी खंड XXI में वर्णित प्रतिबन्धों द्वारा शासित होंगे।
- (ix) “हरित पट्टी” से अभिप्राय है, विकास योजना में दर्शाये गये सैक्टर/मुख्य सड़क के साथ-साथ भूमि की पट्टी जो भविष्य में सैक्टर/मुख्य सड़क को मुख्य रूप से चौड़ा करने के लिए हो या पर्यावरण जैसे शोर, धूम्रपान, घातक धूल कण इत्यादि प्रतिरोधक के रूप में।
 - (x) “फर्श क्षेत्र अनुपात (फ0क्षे0अनु0)” से अभिप्राय है, किसी भवन की सभी मंजिलों के कुल फर्श और स्थल के कुल क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में दर्शाया गया अनुपात;
 - (xi) “वर्ग आवास” से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैट के रूप में डिजाइन किये गये भवन या अनुषंगी अथवा सम्बद्ध भवन होंगे, जिनमें सामुदायिक सुविधायें, सार्वजनिक सुविधायें और जन उपयोगितायें तथा खरीदारी क्षेत्र शामिल हैं, जो निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा द्वारा निर्धारित और अनुमोदित हों;
 - (xii) “भारी उद्योग” से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सरकारी या अर्धसरकारी या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (मशीनरी इत्यादि, प्लांट की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिभाषित हो);
 - (xiii) “सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई” से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2000 के अनुबन्ध में शामिल उद्योगों की श्रेणी तथा जो हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किया जाये;
 - (xiv) “टांड या तलशिला” से अभिप्राय है, स्वयं कमरे के अन्दर खम्भे के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से आवृत एक खाने जैसा उभार, परन्तु जिसका उभार एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो;
 - (xv) “हल्के उद्योग” से अभिप्राय है, ऐसे उद्योग जिसके कारण हानिकारक या आपत्तिजनक शोर, धुआं, गैस, भोंप या गन्ध धूल, मलनिस्त्राव और कोई अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और बिजली द्वारा चालित हों;

- (xvi) "स्थानीय सेवा उद्योग" से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्मित माल और उत्पादन प्रायः स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस्तेमाल किया जाता हो, उदाहरणार्थ बेकरियां, आईसक्रीम, विनिर्माण, वातित जल, बिजली से चलने वाली आटे की चक्कियां, लॉन्ड्री, ड्राईक्लीनिंग और रंगाई, स्वचालित गाड़ियों, स्कूटर तथा साईकलों की मुरम्मत तथा सर्विस, घरेलू बर्तनों की मुरम्मत, जूते बनाना और उनकी मुरम्मत, ईंधन डिपो आदि बशर्ते कि उन द्वारा किसी ठोस ईंधन का प्रयोग न किया जाता है;
- (xvii) "अटारी" से अभिप्राय है, सामान्य फर्श से ऊपर अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई ढलुआ छत में शेष बचे स्थान पर मध्यवर्ती फर्श, जो भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित करवाई जाती है अथवा अपना ली जाती है;
- (xviii) "वास्तविक तिथि" से अभिप्राय है, निम्नलिखित नियन्त्रित क्षेत्रों की अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि:

क्रम संख्या	नियन्त्रित क्षेत्र का नाम	वास्तविक तिथि
1.	अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/आर.डब्ल्यू.आर. (ए.सी.ए.-II)/ 2007 / 424, दिनांक 9 फरवरी, 2007 द्वारा रिवाड़ी नगर परिषद के चारों ओर घोषित अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र- II जो हरियाणा राजपत्र में दिनांक 9 फरवरी 2007 को प्रकाशित है।	9 फरवरी, 2007
2.	अधिसूचना संख्या पी.सी.-97 / 191, दिनांक 12 मार्च, 1997 द्वारा घोषित बावल का नियन्त्रित क्षेत्र जो हरियाणा राजपत्र में दिनांक 8 अप्रैल, 1997 को प्रकाशित है।	8 अप्रैल, 1997
3.	अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/ बावल/ए.सी.ए.-II/ 2007 / 1622, दिनांक 22 अप्रैल, 2007 द्वारा घोषित बावल का अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र II, III जो हरियाणा राजपत्र में दिनांक 22 अप्रैल 2007 को प्रकाशित है।	20 अप्रैल, 2007
4.	अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/ आर.डब्ल्यू.आर./के.डब्ल्यू.एस./सी.ए.(ख) / 2007 / 425, दिनांक 9 फरवरी, 2007 द्वारा अधिसूचित प्राथमिक विद्यालय खालियावास के आस-पास नियन्त्रित क्षेत्र	9 फरवरी, 2007
5.	अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/आर.ई.-बी.डब्ल्यू.एल (ए.सी.ए.-IV)/ 2013 / 244, दिनांक 23 जनवरी, 2013 द्वारा अधिसूचित नगरपालिका नगर बावल के चारों ओर अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र -IV	23 जनवरी, 2013
6.	अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/आर.ई.-एम.बी.आई.आर./सी.ए.-II)/ 2013 / 245, दिनांक 23 जनवरी, 2013 द्वारा अधिसूचित नगरपालिका नगर धारुहेड़ा के चारों ओर अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र -II	23 जनवरी, 2013
7.	अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/आर.ई.-एम.बी.आई.आर./सी.वी./ 2013 / 246, दिनांक 23 जनवरी, 2013 द्वारा अधिसूचित नगरपालिका नगर बावल के चारों ओर अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र -V	23 जनवरी, 2013
8.	अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/आर.ई.-एम.बी.आई.आर./सी.ए.-III)/ 2013 / 247, दिनांक 23 जनवरी, 2013 द्वारा अधिसूचित नगरपालिका नगर रेवाड़ी के चारों ओर अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र -III	23 जनवरी, 2013
9.	अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/आर.ई.-एम.बी.आई.आर./सी.ए.-IV)/ 2013 / 248, दिनांक 23 जनवरी, 2013 द्वारा अधिसूचित नगरपालिका नगर रेवाड़ी के चारों ओर अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र -IV	23 जनवरी, 2013

- (xix) "मध्यम उद्योग" से अभिप्राय है, 'हल्के उद्योग' तथा 'स्थानीय सेवा उद्योग' के अलावा सभी उद्योग और जो खतरनाक गंध तथा दुर्गन्ध न फैलाते हों;
- (xx) "उपयोग गैर अनुरूप" नियन्त्रित क्षेत्र में किसी भूमि अथवा भवन के संबंध में "अनुरूप उपयोग" से अभिप्राय है, ऐसी भूमि अथवा भवन का वर्तमान उपयोग जो विकास योजना में क्षेत्र के उस भाग के लिए निर्दिष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विपरीत हो;
- (xxi) "हानिकारक या खतरनाक उद्योग" से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूंजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक धूआं, शोर, स्पन्दन, दुर्गन्ध, अप्रिय या हानिकारक मलनिस्त्राव, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य खतरनाक तत्व शामिल हों।

- (xxii) "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा भवन" से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए अपेक्षित हो, जैसा जल सप्लाई, जल निकास, बिजली, दूरभाष, डाक तथा तार एवं परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नगरपालिका सेवा;
- (xxiii) "नियमों" से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम 1965;
- (xxiv) "ग्रामीण उद्योग योजनाएं" से अभिप्राय है, उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योग योजनाओं के अधीन जिसको पंजीकृत किया गया है, औद्योगिक इकाई है।
- (xxv) "सैक्टर क्षेत्र" अथवा "कॉलोनी क्षेत्र" से अभिप्राय है, सैक्टर या कॉलोनी का क्षेत्र ड्राईंग में दिखाये अनुसार होगा।

व्याख्या:

- (1) इस परिभाषा में "सैक्टर क्षेत्र" या "कालोनी क्षेत्र" से अभिप्राय होगा, सैक्टर या कालोनी या क्षेत्र जो ड्राईंग पर तथा कालोनी/सैक्टर की अनुमोदित विन्यास योजना पर दर्शाये गये मुख्य सड़क प्रणाली में प्रतिबन्धित है, इसमें सैक्टर या कालोनी, जैसे भी स्थिति हो, में भवन विकास के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र शामिल नहीं हैं।
- (2) औद्योगिक कालोनी/सैक्टर से भिन्न कालोनी या सैक्टर की विन्यास योजना में, सड़को, खुले स्थानों, विद्यालयों, जन तथा सामुदायिक भवन तथा अन्य सामूहिक उपयोगों के लिए आरक्षित भूमि, कालोनी/सैक्टर के अधीन भूमि के कुल क्षेत्र के 45 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
- (xxvi) "सैक्टर सघनता और कॉलोनी सघनता" से अभिप्राय है उस सैक्टर क्षेत्र तथा कॉलोनी क्षेत्र में, जैसी भी स्थिति हो, प्रति हैक्टेयर व्यक्तियों की संख्या।

व्याख्या:

सैक्टर सघनता या कालोनी सघनता की संगणना के प्रयोजन के लिए यह माना जायेगा कि सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 55 प्रतिशत आवासीय प्लॉटों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें ग्रुप आवास के अधीन क्षेत्र शामिल होगा तथा कि प्रत्येक भवन प्लॉट प्रत्येक तीन निवास इकाइयों में 4.5 व्यक्ति प्रति निवास इकाई या 13.5 व्यक्ति भवन प्लॉट या जो कालोनी/ग्रुप आवास समूह की अंचल योजना में सम्मिलित है सहित औसत पर होगा। यद्यपि, दुकान एवं प्लॉट के मामले में केवल एक निवास इकाई मानी जायेगी।

- (xxvii) "स्थल आच्छादन" से अभिप्राय है, भूतल पर निर्मित क्षेत्र और स्थल के बीच प्रतिशतता द्वारा दर्शाया गया अनुपात;
- (xxviii) "लघु उद्योग" से अभिप्राय है, एक ऐसी औद्योगिक इकाई, जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत हो;
- (xxix) "कृषि उपयोग साधन" से अभिप्राय होगा, ऐसी विकास तथा गतिविधियां, जो कृषि संबंधी कार्यों को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प चैम्बर, वायु चक्की, सिंचाई, नाले, पक्के प्लेटफार्म, बाढ़ लगाना तथा चारदीवारी बनाना, जो 4 फुट की उंचाई से अधिक न हो तथा अधिकतम 3 फुट उंची बाढ़ सहित हो जल नलके आदि;
- (xxx) "अधिनियम", "कालोनी", "उप-निवेशक", "विकास योजना", "सैक्टर" और "सैक्टर योजना" अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 41) और पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम 1965 में दिया गया है;
- (xxxi) "नगर सघनता" से अभिप्राय है, नगर में प्रति हैक्टेयर व्यक्तियों की संख्या;
- (xxxii) "शहरीयोग्य सीमा" से अभिप्राय है, सैक्टर के भूमि उपयोगों को परिभाषित करते हुए विकास के लिए प्रस्तावित शहरीयोग्य क्षेत्र में आने वाली सीमा तथा जिसमें परिधीय सड़क तथा हरित पट्टी शामिल हैं।
- (xxiii) किन्हीं अन्य शब्दों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम, तथा नियमों में दिया गया है;

III मुख्य भूमि उपयोग/अंचल:

1. (i) रिहायशी अंचल
- (ii) वाणिज्यिक अंचल
- (iii) औद्योगिक अंचल

- (iv) परिवहन तथा संचार अंचल
- (v) जनउपयोगिता अंचल
- (vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल (संस्थागत अंचल)
- (vii) खुले स्थान अंचल
- (viii) कृषि अंचल
- (ix) प्राकृतिक संरक्षण अंचल

(2) मुख्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण "परिशिष्ट क" के अनुसार है इन आंचलिक विनियमों के साथ जोड़े गये हैं।

IV सेक्टरों में विभाजन:

उपर्युक्त विनियमन-III में क्रम संख्या (i) से (vii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो भवन परियोजनार्थ भूमि उपयोग है, उन्हें दर्शाये अनुसार सेक्टरों में विभाजित किया गया है, इन सेक्टरों की मुख्य सड़कों के आरक्षण द्वारा हदबन्दी की हुई है और प्रत्येक सेक्टर को ड्राईंग में दिखाये अनुसार एक निश्चित संख्या दी गई है।

V मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग संबंधी ब्यौरे :

मुख्य, सहायक एवं गौण उपयोग के लिए इन विनियमों/नियमों को अन्य उपेक्षाओं के अन्तर्गत संबंधित मुख्य भूमि उपयोग अंचल में अनुमति दी जा सकती है, उनकी सूची परिशिष्ट ख पर दी गई है जो इन विनियमों के साथ जोड़े गये हैं।

VI विकास के लिए अनुपयुक्त सेक्टर :

विभिन्न सेक्टरों में भवन परियोजनार्थ संबंधित उपयोग के लिए आरक्षण होने पर भी निदेशक, नियंत्रित क्षेत्र के सघन एवं किफायती विकास के दृष्टिगत किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक जल सप्लाई, जल मल निकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, इन सेक्टरों में, उसकी तसल्ली तक सुनिश्चित रूप में उपलब्ध नहीं हो जाती।

VII सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक सेक्टर तथा पट्टी / स्ट्रिप:

- (1) जो सेक्टर वाणिज्यिक उपयोग हेतु आरक्षित किए गए हैं उनका 10 प्रतिशत तक का क्षेत्र निजी उप निवेशकों द्वारा 1975 का अधिनियम संख्या 8 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद सेक्टर क्षेत्र विकसित करने की अनुमति होगी। बाकि 90 प्रतिशत क्षेत्र केवल सरकार या सरकार उपक्रम या सरकार द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक अभिकरण द्वारा ही विकसित किया जाएगा।
- (2) उपर्युक्त खण्ड (1) के उपबंध के होते हुए सरकार, किसी भी समय स्वयं या इसकी उपयुक्त सूचित एंजिसियों द्वारा विकास हेतु किसी अन्य सेक्टर को आरक्षित कर सकती है।

VIII मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण:

(1) ड्राईंग में चिन्हित की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण निम्न प्रकार से किया जायेगा:

क्रम संख्या	वर्गीकरण	भूमि आरक्षण	टिप्पणी
मुख्य सड़क			
I	वी.एन.-1	दोनों ओर पर 60 मीटर हरित पट्टी सहित 60 मीटर चौड़ाई	राष्ट्रीय राजमार्ग-48
II	वी.एन.-2	दोनों ओर पर 50 मीटर हरित पट्टी सहित वर्तमान चौड़ाई	राष्ट्रीय राजमार्ग-71
III	वी.एस.	दोनों ओर पर 30 मीटर हरित पट्टी सहित 60 मीटर चौड़ाई	राज्य राजमार्ग
IV	वी.बी.	दोनों ओर पर 100 मीटर हरित पट्टी सहित 100 मीटर चौड़ाई	बी.आर.टी. वाला सम्पूर्ण रूट बावल परिधीय सड़क
V	वी.-1	दोनों ओर पर 50 मीटर हरित पट्टी सहित 80 मीटर चौड़ाई	एम.बी.आई.आर. परिधीय सड़क सहित
VI	वी.-1 (क)	दोनों ओर पर 50 मीटर हरित पट्टी सहित 80 मीटर चौड़ाई	बी.आर.टी. वाला सम्पूर्ण रूट
VII	वी.-2	दोनों ओर पर 50 मीटर हरित पट्टी सहित 60 मीटर चौड़ाई	

VIII	वी.-2 (क)	दोनों ओर पर 50 मीटर हरित पट्टी सहित 60 मीटर चौड़ाई	बी.आर.टी. वाला सम्पूर्ण रूट
IX	वी.-2 (ख)	दोनों ओर पर 30 मीटर हरित पट्टी सहित 60 मीटर चौड़ाई	बी.आर.टी. वाला सम्पूर्ण रूट
उप-मुख्य सड़क			
X	वी.-2 (ग)	60 मीटर चौड़ी	
XI	वी.-2 (घ)	60 मीटर चौड़ी	बी.आर.टी. वाला सम्पूर्ण रूट
XII	वी.-3	दोनों ओर पर 30 मीटर हरित पट्टी सहित 45 मीटर चौड़ाई	बी.आर.टी. वाला सम्पूर्ण रूट
XIII	वी.-3 (क)	45 मीटर चौड़ी	

- (2) अन्य सड़कों की चौड़ाई और अनुरेखण सेक्टर योजना के अनुसार अथवा कालोनियों की अनुमोदित अभिविन्यास योजना के अनुसार होगी।
- (3) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा निजी उपनिवेशकों द्वारा विकसित किए जाने वाले सैक्टर/ कालोनी के लिए तैयार योजनाओं का अनुमोदन करते समय मुख्य सड़कों तथा निकटवर्ती हरित पट्टी यदि कोई हो के अधीन पड़ने वाले क्षेत्र का केवल 50 प्रतिशत का लाभ प्लॉटिड/ग्रुप आवास कालोनी में प्लॉटिड क्षेत्र/ फर्श क्षेत्र अनुपात के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। तथापि, सैक्टर योजना में शुद्ध योजनागत क्षेत्र में शामिल सड़कों की स्थिति में पूर्ण फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ दिया जायेगा। वाणिज्यिक कालोनी तथा सूचना प्रौद्योगिकी पार्क साइबर सिटी की स्थिति में स्थल के कुल क्षेत्र के 10 प्रतिशत फर्श अनुपात का लाभ या हरित पट्टी तथा सैक्टर सड़क में आने वाले क्षेत्र, इसमें से जो भी कम हो, दिया जाएगा।

IX नान-मोटोराइज्ड यातायात तथा पैदल चलने वालों के लिए सुविधाएं :-

सैक्टरों का विकास तथा विकास कार्य करते समय नान-मोटोराइज्ड यातायात का उपयोग बढ़ाते हुए सचेतन प्रयासों का सूकर बनाया जाएगा तथा पैदल संचालन के लिए पर्याप्त स्थान सृजित करने के भी प्रयास किए जाएंगे।

X विद्यमान या भूमि उपयोग में वैध परिवर्तन की अनुमति प्राप्त अननुरूप उपयोग:

- (1) विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न अंचलो में स्थित विद्यमान परियोजना के संबंध में निदेशक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियत अवधि के लिए ऐसे अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, किन्तु यह अवधि विकास योजना के प्रकाशन को तिथि से दस वर्ष से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी :-
- (क) उस स्थल को निदेशक द्वारा बाह्य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभागों को देने का वचन देता है जब उसे निदेशक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये।
- (ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्त्राव के निर्वहन के लिए सन्तोषजनक व्यवस्था करें; तथा
- (ग) अननुरूप उपयोग के क्षेत्र में वर्तमान परियोजना में किसी प्रकार के विस्तार की अनुमति नहीं होगी।
- (2) विकास योजना में अनुरूप उपयोग अंचल से भिन्न भूमि उपयोग अनुमति के वैध परिवर्तन वाली परियोजना तथा अंचलो में स्थित वर्तमान परियोजनाओं के संबंध में ऐसे अननुरूप उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते कि सम्बद्ध भवन का स्वामी :-
- (क) उस स्थल को निदेशक द्वारा बाह्य विकास के लिए उस द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभागों को देने का वचन देता है जब उसे निदेशक द्वारा इस निमित्त ऐसा करने के लिए कहा जाये तथा
- (ख) अंतरिम अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार बहिःस्त्राव के निर्वहन के लिए सन्तोषजनक व्यवस्था करें।

XI अननुरूप उपयोग बन्द करना :

- (1) यदि किसी भूमि का अनुरूप उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार बन्द रहा हो तो उसे समाप्त हुआ समझा जायेगा और अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनःउपयोग या पुनःविकास की अनुमति दी जायेगी।
- (2) यदि अनुरूप उपयोग भवन, आग, बाढ़, विस्फोट, भूकम्प, लड़ाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से पुनःउत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने की अनुमति दी जायेगी।
- (3) खण्ड X के अन्तर्गत नियत अवधि के समाप्त होने के बाद, ऐसी भूमि केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनःविकसित करने या उपयोग में लाने की अनुमति दी जायेगी।
- (4) खण्ड X (1) के अधीन नियत अवधि की समाप्ति के बाद, भूमि केवल अनुरूप उपयोग के लिए पुनःविकसित या उपयोग करनी अनुज्ञात की जाएगी।

XII नियन्त्रित क्षेत्रों में ईट भट्टे :-

नियन्त्रित क्षेत्रों में ईट भट्टों के स्थल समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सम्बन्धित पालिसी/मार्ग-दर्शनों द्वारा शासित होंगे।

XIII सेक्टर योजना और आंचालक योजना के अनुरूप विकास:

विनियम-X में प्रावधान को छोड़कर, कोई मुख्य भूमि उपयोग जिसमें भूमि विद्यमान है, को भवन निर्माण परियोजनार्थ उपयोग और विकसित करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि प्रस्तावित उपयोग और विकास, सेक्टर योजना और आंचालक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना में दिखाये गये ब्यौरे के अनुसार न हो।

XIV अनुमोदित अभिन्यास या आंचालक योजना का भाग बनने वाले विशिष्ट स्थल:

प्लॉट पर भवन निर्माण या पुनःनिर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि—

- (i) प्लॉट अनुमोदित कालोनी का भाग न हो या प्लॉट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम XVIII में यथा उपबन्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा
- (ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लॉट की स्थिति तक बनाई गई सड़क के माध्यम से पहुंच न हो या सड़क न बनी हो।

XV विभिन्न प्रकार के भवनों कालोनियों के लिए न्यूनतम मानक:

- (1) विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए प्लॉटों के न्यूनतम आकार निम्न अनुसार होंगे:-

(i)	रिहायशी प्लॉट	50 वर्ग मीटर
(ii)	सरकार द्वारा अनुमोदित आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास या गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए आवास स्कीम में रिहायशी प्लॉट	35 वर्ग मीटर
(iii)	दुकान एवं रिहायशी प्लॉट	100 वर्ग मीटर
(iv)	शॉपिंग बूथ जिनमें सामने बरामदा या पत्थर या ईट का पैदल मार्ग शामिल हो	20 वर्ग मीटर
(v)	स्थानीय सेवा उद्योग प्लॉट	100 वर्ग मीटर
(vi)	हल्के उद्योग प्लॉट	250 वर्ग मीटर
(vii)	मध्यम उद्योग प्लॉट	8000 वर्ग मीटर

- (2) प्राईवेट विकासकों द्वारा कालोनियों के विकास के लिए क्षेत्र मानक निम्न अनुसार होंगे :-

कालोनी की किस्म	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
आवासीय प्लॉटिड कालोनी	न्यूनतम 50 एकड़

आवासीय ग्रुप आवास कालोनी	स्वतन्त्र ग्रुप आवास स्कीम तथा अनुज्ञप्त कालोनियों के भाग रूप स्थल के लिए न्यूनतम 5 एकड़। तथापि, यदि कोई ग्रुप आवास स्कीम हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा प्रारम्भ की जाती है, तो ग्रुप आवास स्थल का आकार स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट होगा।
वाणिज्यिक कालोनी	न्यूनतम 2 एकड़ से अधिक 4 एकड़
औद्योगिक कालोनी	न्यूनतम 25 एकड़

टिप्पण : अनुज्ञप्त ग्रुप आवास कालोनी के अधीन क्षेत्र, अन्यथा विनिर्दिष्ट सैक्टर क्षेत्र का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

XVI विभिन्न प्रकार के भवनों के अधीन आच्छादित स्थल, ऊँचाई और आकार :

स्वतन्त्र रिहायशी और औद्योगिक प्लॉट पर बनाये जाने वाले भवनों का निर्मित क्षेत्र और ऊँचाई नियमों के अध्याय VII में उल्लेखित उपबन्धों के अनुसार होगी। अन्य वर्गों के मामले में विनियम XVIII के अन्तर्गत लगाये जाने वाले वास्तुकला नियन्त्रण के अनुसार अधिकतम निर्मित क्षेत्र और फर्श क्षेत्र अनुपात निम्नानुसार होगा:-

क्रमांक	उपयोग की किस्म	अधिकतम भू-तल आच्छादन	अधिकतम फर्श क्षेत्र अनुपात	तहखाने में अनुमत की जाने वाली पंक्ति तथा उपयोग
1	ग्रुप आवास	35 प्रतिशत	1.75	पार्किंग तथा सेवा की व्यवस्था सहित 4 स्तर तहखाना अनुज्ञात किया जाएगा यदि यह जन स्वास्थ्य, अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता है।
2.	सरकारी कार्यालय	25 प्रतिशत	1.5	पार्किंग तथा सेवा की व्यवस्था सहित 3 स्तर तहखाना अनुज्ञात किया जाएगा यदि यह जन स्वास्थ्य, अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता है।
3.	वाणिज्यिक (क) संघटित कारपोरेट	40 प्रतिशत	1.5-1.75 (जोनिंग प्लान के अनुसार)	पार्किंग तथा सेवा की व्यवस्था सहित 4 स्तर तहखाना अनुज्ञात किया जाएगा यदि यह जन स्वास्थ्य, अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता है।
	(ख) व्यक्तिगत एस.सी.ओ.	100 प्रतिशत	3.0	3 मीटर से अनधिक एकल तहखाना भण्डारण, लिफ्ट का मशीन कक्ष, रिकार्ड, गोदाम तथा स्ट्रांग कक्ष के लिए तथा स्थल का केवल अनुषंगी अनुज्ञेय उपयोग अनुज्ञात किया जाएगा तथा किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
	(ग) बूथ	100 प्रतिशत	1.0	3 मीटर से अनधिक एकल तहखाना भण्डारण के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।
4.	भाण्डागार	60 प्रतिशत	0.75	कोई तहखाना अनुमत नहीं किया जाएगा।

टिप्पण: भूगत तल आंचलिक योजना में भूगत तल, फर्श क्षेत्र अनुपात से मुक्त अनुमत होगा। भूगत-तल राष्ट्रीय भवन संहिता के उपबन्धों के अनुसार भण्डारण सामग्री के लिए उपयोग किया जायेगा।

XVII भवनों की अगली ओर पिछली ओर भवन पंक्ति :

यह पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1965, के नियम 51, 52 तथा 53 में उपबन्धित अनुसार होगी।

XVIII वास्तुकला संबंधी नियंत्रण:

प्रत्येक भवन पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1965, के नियम 50 के अन्तर्गत बनाये वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।

XIX कृषि अंचल में ढील:

कृषि अंचल में पड़ी किसी भूमि के मामले में, सरकार इस विकास योजना के उपबन्ध में निम्नलिखित ढील दे सकती है:-

- (क) भूमि के आवासीय अथवा औद्योगिक उपनिवेश में उपयोग एवं विकास के लिए बशर्ते कि उपनिवेशक ने यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उक्त उपयोग एवं विकास के लिए खरीदी हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।
- (ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि के उपयोग के लिए (औद्योगिक कालोनी से भिन्न)

बशर्ते कि:-

- वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि खरीदी गई हो;
- सरकार को इस बात से संतुष्टि है कि उद्योग की आवश्यकता इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक स्थल के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;
- भू-स्वामी, यथा अपेक्षित नियमों के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करता है;
- भू-स्वामी, निदेशक द्वारा यथा निर्धारित अनुपातिक प्रभार जब कभी उस द्वारा इस निमित्त मांग की जाये, अदा करने की प्रतिज्ञा करता है और अंतरिम अवधि में मल निकास की संतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्या: विनियम में शब्द 'क्रय' (खरीद) का अभिप्राय पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को प्राप्त करना है तथा न कि पट्टानामा या क्रय हेतु इकरारनामा आदि।

- (ग) स्थल रक्षा संथापनाओं, यदि कोई हो, के आस-पास रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के अधीन अधिसूचित प्रतिबन्धित पट्टी में नहीं आयेगा।

XX सघनता:

प्रत्येक आवासीय सैक्टर इसके लिए ड्राईंग में दर्शायी एवं निर्धारित सैक्टर सघनता के अनुसार विकसित किया जायेगा परन्तु सैक्टर की विहित सघनता में किसी भी ओर अधिक से अधिक 20 प्रतिशत की विभिन्नता की अनुमति होगी।

XXI कृषि अंचल में आबादी देह के बाहर फार्म गृह की व्यवस्था:

फार्म गृह भूस्वामी (स्वामियों) के केवल वास्तविक उपयोग के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि उसके पास किसी शहरी क्षेत्र में अपना गृह न हो क्योंकि कृषि जोन में फार्म गृहों की अनुज्ञात करने के लिए वास्तविक उद्देश्य फार्म के लघु भाग पर किसानों की आवास आवश्यकता को पूरा करता है ताकि वह उस फार्म पर रहते समय अपनी कृषि उपज का ध्यान रख सके। अतः कृषि अंचल में आबादी देह के बाहर फार्म गृह की अनुमति, निम्नलिखित शर्तों पर दी जाये, यदि भूमि का क्षेत्र दो एकड़ या इससे अधिक हो:-

	फार्म हाऊस का आकार	आवासीय इकाई का मुख्य भवन	मुख्य आवासीय इकाई का अनुषंगी भवन
(i) निर्मित क्षेत्र	न्यूनतम दो एकड़ किन्तु विकास योजना के अनुसार सड़क आरक्षण/प्रस्तावित सड़क चौड़ी करने के अधीन आने वाले क्षेत्र के लिए सी.एल.यू. अनुमति नहीं मानी जाएंगी तथापि, कुल क्षेत्र हरित पट्टी/प्रतिबन्धित पट्टी पड़ने वाले क्षेत्र तथा 2 एकड़ के लागू क्षेत्र से कृषि जोन में पड़ने वाले क्षेत्र को निकालने के बाद 1.5 एकड़ से कम नहीं होगा।	250 वर्ग गज के समकक्ष रिहायशी प्लॉट को यथा लागू।	फार्म की भूमि का एक प्रतिशत (मजदूरों/नौकरों के क्वार्टरों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं किया जायेगा)
	3 एकड़	375 वर्ग गज के समकक्ष रिहायशी प्लॉट को यथा लागू।	—सम—
	4 एकड़ तक और अधिक	500 वर्ग गज के समकक्ष रिहायशी प्लॉट को यथा लागू।	—सम—
(ii) ऊंचाई तथा मंजिल		11 मीटर, तीन मंजिल	4 मीटर, एक मंजिल

- (iii) दूरी: चारों ओर पर कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 10 मीटर दूर बशर्ते कि यदि फार्म हाऊस से संबद्ध भूमि सड़क के साथ लगती है, तो गृह का निर्माण सड़क के किनारे से कम से कम निम्नलिखित दूरी पर किया जायेगा:-

- (क) जहां सड़क अनुसूचित सड़क का बाईपास या द्रुत मार्ग है। 100 मीटर
- (ख) जहां सड़क अनुसूचित सड़क है अथवा जैसा कि विकास योजना में दर्शाया गया है। 30 मीटर
- (ग) कोई अन्य सड़क 10 मीटर
- (iv) **पहुँच सड़क:** कोई राजस्व रास्ता/सड़क जैसा कि राजस्व रिकार्ड में वर्णित है।
- (v) **तहखाना:** अधिकतम भूतल आच्छादन सीमा तक तहखाने के लिए अनुमति दी जायेगी, परन्तु तहखाने में शौचालय और स्नानगृह बनाने की अनुमति नहीं होगी।
- (vi) **पुश्तवान, अटारी तथा परछती तल:** पुश्तवान, अटारी और परछती तल की अनुमति भवन के भीतर उक्त प्रतिबन्धों और इन जोनिंग विनियमों तथा नियमों खण्ड-II में दी गई परिभाषा में दिये गये प्रतिबन्धों के अन्तर्गत दी जायेगी।
- (vii) **सेवाएं, जल आपूर्ति तथा जल निकास**
- (क) यदि फार्म गृह का निर्माण किया जाता है, तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीने योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।
- (ख) डेरी फार्म के मामले में छायावान की सफाई हेतु खुली मल निकास नालियां अथवा ढकी हुई नालियों का प्रबन्ध किया जाये, सभी भवनों के मामले में वर्षा के पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था की जानी है।
- (ग) नियमों के उपबन्धों के अनुसार मनुष्य और पशुओं के मल निस्तारण के लिए मलाशय की व्यवस्था की जाये।
- (घ) मलाशय और खुले कुएं अथवा नलकूप के बीच दूरी नियमों में यथा उपबन्धित अनुसार होगी:
- (viii) स्वामी को मुख्य निवास इकाई तथा उसके अनुषंगी भाग के चारों ओर चार दीवारी का निर्माण करना अनुज्ञात किया जाएगा तथा फार्म के बाकी क्षेत्र के चारों ओर कंटीली तारों की बाड़ लगाना अनुज्ञात किया जाएगा।
- (ix) फार्म गृह की स्थापना के लिए सी.एल.यू. अनुज्ञा केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा यथा घोषित अधिक शोषित या संकटकालीन क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्र में विचारा जाएगा।

परन्तु सरकार कृषि अंचल के उचित उपयोग के लिए राज्य सरकार/राज्य अभिकरण द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के लिए फार्म गृह के न्यूनतम आकार में संशोधन कर सकती है।

XXII सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयां तथा साइबर पार्क/साइबर सिटी के लिए उपबन्ध:

(i) अवस्थिति:

- (क) सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयां केवल औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक अंचलों में अवस्थित होंगी।
- (ख) साइबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क संघटित विकास के रूप में सैक्टर सड़क के साथ लगते हुए औद्योगिक क्षेत्र अथवा औद्योगिक अंचल में अवस्थित होंगे। यद्यपि, ऐसे पार्कों में कोई विनिर्माण कर रही इकाइयां अनुज्ञात नहीं होंगी।
- (ग) साइबर सिटी की अवस्थिति सरकार द्वारा विनिश्चय किया जायेगा।

(ii) आकार:

क्रम संख्या	प्रकार	आकार
1	सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई	1 से 5 एकड़
2	साइबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क	5 से 15 एकड़
3	साइबर सिटी	न्यूनतम 50 एकड़

(iii) विविध:

I पार्किंग:

- (क) साइबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाइयों तथा साइबर सिटी में प्रत्येक 40 वर्गमीटर फर्श क्षेत्रफल के लिए एक समकक्ष कार स्पेस पार्किंग सुविधायें प्रदान की जायेंगी।
- (ख) पार्किंग की अपेक्षा को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए चार स्तरीय तल खाना अनुमत किया जायेगा जोकि जन स्वास्थ्य समाशोधन के अध्यधीन होगा।

II अन्य क्रियाकलाप:

- (क) आनुषंगिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे कि बैंक रैस्टोरैन्ट, इंश्योरेंस ऑफिस इत्यादि के लिए साइबर पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के पूर्ण क्षेत्र के 4 प्रतिशत के निर्बन्धन के अधीन रहते हुए अनुमति दी जायेगी;
- (ख) साइबर सिटी के क्षेत्र में ग्रुप हाऊसिंग के लिए केवल 5 प्रतिशत अनुज्ञात होगा तथा साइबर सिटी के कुल क्षेत्र का 4 प्रतिशत वाणिज्यिक/संस्थागत उपयोगों के लिए अनुज्ञात होगा;
- (ग) साइबर सिटी में रिहायशी प्लॉटों के विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी;
- (घ) साइबर सिटी प्रोजेक्ट यदि कृषि अंचल में अनुज्ञप्त हो तो उद्यमी पानी सप्लाई तथा अन्य सुविधायें जैसे कि मल निकास, ड्रेनेज इत्यादि को निपटाने का प्रबन्ध करेगा।

III सरकार कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकती है जैसा कि समय-समय पर आवश्यक समझें।

- XXII संचार टावरों की स्थापना :** नियंत्रित क्षेत्र के अन्दर मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए दिनांक 13 जनवरी, 2012 की नीति जो समय-समय पर संशोधित की जा सकती है, के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- XXIV अफोरडेबल ग्रुप आवास :** विकास योजना के आवासीय जोन के भीतर अफोरडेबल ग्रुप आवास परियोजनाओं के लिए अनुमति समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 19 अगस्त, 2013 की नीति के अनुसार दी जाएगी।
- XXV भूकम्पीय आपदा से सुरक्षा :** विकास योजना क्षेत्र में सभी विकास/भवन गतिविधियों को भारतीय मानक आई.एस. 1893, के भूकम्पीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार विकास योजना में भूकम्पीय गतिविधियों की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए "समग्र शहरी विकास घटना की सम्भाव्यता की उक्त तीव्रता के विरुद्ध सुरक्षा के लिए तथा भवन तथा अवसंरचना में अपेक्षित भूकम्पीय मुकाबला करने के लिए बढ़ावा देने के लिए जांच की जाएगी जो आवश्यक पाई जाए।"
- XXVI सैक्टर/कालोनी में भूतन्त्र विसर्जन की व्यवस्था :** री-साइकल पानी के प्रयोग को बढ़ावा देने की धारणा शून्य विर्जन पर सभी सैक्टरों/कालोनियों में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।
- XXVII विकास योजना में ढील:** सरकार अत्यन्त कठिनाई की दशा में अथवा वास्तविक तिथि से पूर्व निर्मित किसी ढांचे को बचाने की दृष्टि से विकास प्रभारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य शर्तों पर वह लगाना उचित, समझे, समान तथा न्याय के सिद्धान्त पर विकास योजना के किसी भी उपबन्धों में ढील दे सकती है।

परिशिष्ट क**भूमि उपयोग का वर्गीकरण**

मुख्य कोड	उपकोड	मुख्य वर्ग	उपवर्ग
100		रिहायशी	पड़ोस पद्धति पर रिहायशी सैक्टर
200		वाणिज्यिक	
	210		परचून व्यवसाय
	220		थोक व्यवसाय
	230		भांडागार और भंडारण
	240		कार्यालय और बैंक जिसमें सरकारी कार्यालय भी शामिल है।
	250		रैस्तरां, होटल तथा अस्थाई बोर्डिंग हाऊस, जिनमें धर्मशाला, पर्यटक गृह आदि जैसे रिहायशी आवास की व्यवस्था वाली सार्वजनिक सहायता संस्थाएँ भी शामिल हैं
	260		सिनेमा एवं वाणिज्यिक आधार पर लोगों के एकत्रित होने वाले अन्य स्थान /टैलीफोन एक्सचेंज आदि
	270		व्यावसायिक स्थापनाएँ
300		औद्योगिक	

310		सेवा उद्योग
320		हल्के उद्योग
330		व्यापक उद्योग
340		भारी उद्योग
400	परिवहन तथा संचार	
410		रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन तथा साइडिंग
420		सड़कें, सड़क परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र
440		हवाई अड्डा / हवाई स्टेशन
450		तार कार्यालय, टैलीफोन एक्सचेंज आदि
460		प्रसारण केन्द्र
470		टेलीविजन केन्द्र
480		संभारण तन्त्र पार्क/आंचल/शुष्क बन्दरगाह जिसमें अन्तर्देशों डिब्बे डिपो तथा भाण्डागार शामिल हैं।
500	जन उपयोगितायें	
510		जल आपूर्ति संस्थापन जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल है
520		जल निकास और सफाई संस्थापनायें जिनमें मलवहन शोधन संयंत्र तथा व्ययन संकर्म भी शामिल है
530		बिजली संयंत्र उपस्टेशन आदि
540		गैस संस्थापना और गैस कार्य
550		टोस मल प्रबन्धन स्थल
600	सरकारी और अर्धसरकारी	
610		सरकारी प्रशासन, सचिवालय/जिला/कार्यालय/तहसील/खण्ड, विधि न्यायालय, जेलें, पुलिस थाने/पुलिस लाइन
620		शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थायें
630		चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थायें
640		मुख्यतः गैर वाणिज्यिक किस्म के थियेटर, आपेरा, गृह, इत्यादि जैसी सांस्कृतिक संस्थायें
650		रक्षा से सम्बन्धित भूमि
700	खुले स्थान	
710		खेलकूद मैदान, स्टेडियम, क्रीड़ा मैदान
720		पार्क
730		हरित पट्टी, बाग तथा अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग
740		कब्रिस्तान, शमशान घाट इत्यादि
750		पैट्रोल पम्प तथा बस क्यू शैल्टर
760		जल निकास/झील/जल रिचार्ज आंचल

770	मेला ग्राउंड, बहु उद्देशीय स्थल
800	कृषि भूमि
810	मार्किट गार्डन, फलोद्यान तथा नर्सरियां
820	कृषि प्रक्रिया के अधीन भूमि, जहां भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी।
830	स्टैपल फसल के अधीन भूमि
840	चराई भूमि तथा चरागाहें
850	वन भूमि
860	मारसी भूमि
870	बंजर भूमि
880	जलमग्न भूमि
890	डैरी फार्मिंग
1000	प्राकृतिक संरक्षण जोन प्राकृतिक संरक्षण जोन में संबंधित कार्यविधियों/गतिविधियां 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसमें सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही अनुमति होगी।

परिशिष्ट ख

मुख्य भूमि उपयोग के अधीन दी गई अनुज्ञेय गतिविधियों सरकार द्वारा अनुमोदित पॉलिसी/पैरामीटर के अनुसार अनुज्ञात की जाएंगी तथा स्थल सैक्टर/ कालोनी योजना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित होंगे।

I रिहायशी अंचल:

- (i) आवासीय
- (ii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद भवन
- (iii) जन उपयोगिता भवन
- (iv) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय जहाँ आवश्यक हो
- (v) स्वास्थ्य संस्थाएँ
- (vi) सिनेमा
- (vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय
- (viii) परचून की दुकानें और रैस्तरां, ढाबा
- (ix) स्थानीय सेवा उद्योग
- (x) गैस/पेट्रोल पम्प
- (xi) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, स्कूटर तथा आटो रिक्शा स्टैंड
- (xii) नर्सरिया और हरित ग्रह
- (xiii) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी – छोटी जरूरतें
- (xiv) सितारा होटल
- (xv) क्लब/सामुदायिक केन्द्र
- (xvi) संचार टावर

- (xvii) मेहमान / बोर्डिंग गृह
- (xviii) कोई अन्य उपयोग जिसका सरकार लोकहित में निर्णय करें।

II. वाणिज्यिक अंचल:

- (i) परचून व्यापार
- (ii) थोक व्यापार
- (iii) भांडागार और भंडारण
- (iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक
- (v) रैस्तरां तथा अस्थाई आवास गृह जिसमें जैसे कि धर्मशाला, पर्यटक गृह आदि रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थान शामिल हैं
- (vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले लोगों के इकट्ठा होने अन्य वाले स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि
- (vii) व्यावसायिक संस्थापनायें
- (viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास
- (ix) स्थानीय सेवा उद्योग
- (x) जन उपयोगिता भवन
- (xi) गैस/पेट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज
- (xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड
- (xii) वाहन खड़े करने के स्थान, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा, आटो/रिक्शा स्टैंड
- (xiv) नगर पार्क
- (xv) संचार टावर
- (xvi) कोई अन्य उपयोग, जिसका सरकार लोकहित में निर्णय करें।

III. औद्योगिक अंचल:

- (i) हल्के उद्योग
- (ii) मध्यम उद्योग
- (iii) हानिकर तथा खतरनाक उपयोग
- (iv) भारी उद्योग
- (v) सर्विस उद्योग
- (vi) भांडागार और भंडारण
- (vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र
- (viii) ट्रक स्टैंड/बस स्टाप, टैक्सी, तांगा और आटो/रिक्शा स्टैंड

- (ix) सार्वजनिक उपयोगिता, सामुदायिक भवन, परचून की दुकानें, बैंक, ढाबा, रेस्टोरेंट, दो/तीन /पांच सितारा होटल तथा बीमा कार्यालय जिनका कुल क्षेत्रफल सैक्टर के कुल क्षेत्रफल के तीन प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधधीन निम्न अनुसार है :

क्रम संख्या	सुविधाओं का नाम	क्षेत्र		क्षेत्र में सुविधाओं की संख्या	वाणिज्यिक घटक	अधिकतम भूतल अच्छादन	फर्श क्षेत्र अनुपात	पहुँच मार्ग
		न्यूनतम	अधिकतम					
1.	ढाबा	500 वर्ग मीटर	1000 वर्ग मीटर	2	50 वर्ग मीटर	40 प्रतिशत	0.40 प्रतिशत	न्यूनतम 18 मीटर
2.	रेस्टोरेंट	1000 वर्ग मीटर	2000 वर्ग मीटर	2	10 प्रतिशत	30 प्रतिशत	1.50 प्रतिशत	न्यूनतम 18 मीटर
3.	दो/तीन सितारा होटल	1.0 एकड़	2.5 एकड़	2	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	वाणिज्यिक पालिसी के अनुसार	न्यूनतम 24 मीटर
4.	पाँच सितारा होटल	2.5 एकड़	4.0 एकड़	1	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	वाणिज्यिक पालिसी के अनुसार	सर्विस सड़क के प्रावधान के साथ सैक्टर विभाजन सड़क

- (x) गैस/पेट्रोल पम्प तथा सर्विस गैरेज
- (xi) निदेशक द्वारा अनुमत तरल पेट्रोलियम, गैस गोदाम
- (xii) साइबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक ईकाइयां
- (xiii) स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि अस्पताल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, क्लीनिक निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	सुविधाओं का नाम	क्षेत्र		क्षेत्र में सुविधाओं की संख्या	रिहायशी घटक	अधिकतम भूतल अच्छादन	फर्श क्षेत्र अनुपात
		न्यूनतम	अधिकतम				
1.	अस्पताल	2.5 एकड़	5.0 एकड़	1	15 प्रतिशत	33 प्रतिशत	1.00 प्रतिशत
2.	डिस्पेंसरी	1.0 एकड़	1.5 एकड़	1	15 प्रतिशत	33 प्रतिशत	1.00 प्रतिशत
3.	नर्सिंग होम	250 वर्ग मीटर	500 वर्ग मीटर	2	—	60 प्रतिशत	1.00 प्रतिशत
4.	क्लीनिक	250 वर्ग	500 वर्ग	2	—	60 प्रतिशत	1.00 प्रतिशत

		मीटर	मीटर				
--	--	------	------	--	--	--	--

(xiv) औद्योगिक कालोनी की योजना के लिए आन्तरिक भूमि उपयोग वितरण निम्न अनुसार है :-

क्रम संख्या	कालोनी/पार्क के कुल क्षेत्र की प्रतिशतता	भूमि उपयोग
1	50 एकड़ आकार तक	इस श्रेणी-औद्योगिक-45 प्रतिशत (न्यूनतम) में नियमों में प्रस्तावित कोई परिवर्तन नहीं, आवासीय/आवास का उपयोग 15 प्रतिशत (अधिकतम), वाणिज्यिक-5 प्रतिशत (अधिकतम)
2	50-200 एकड़ तक	औद्योगिक-40 प्रतिशत (न्यूनतम); आवासीय/ हाऊसिंग उपयोग-अफोर्डेबल/गुप हाऊसिंग/प्लॉट्स का 20 प्रतिशत (अधिकतम); वाणिज्यिक-5 प्रतिशत (अधिकतम)।
3	200 एकड़ से अधिक	औद्योगिक-35 प्रतिशत (न्यूनतम), आवासीय/हाऊसिंग को मिलाकर मिश्रित उपयोग 30 प्रतिशत, अफोर्डेबल/गुप हाऊसिंग/प्लॉट्स को मिलाकर 25 प्रतिशत (अधिकतम), वाणिज्यिक-5 प्रतिशत (अधिकतम)

(xv) संचार टावर

(xvi) तैयार मिश्रण कंक्रीट संयंत्र, बेट मिश्रण संयंत्र, गर्म मिश्रण संयंत्र इत्यादि

(xvii) धर्मकांटा

(xviii) सर्विस गैरेज, विक्रय/प्रदर्शन केन्द्र एवं सर्विस गैरेज।

(xix) कोई अन्य उपयोग जिसका सरकार लोकहित में निर्णय करें।

IV परिवहन तथा संचार अंचल:

- रेलवे यार्ड रेलवे स्टेशन और साईडिंग
- परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन, डिपो/बस स्टैंड और पार्किंग क्षेत्र
- हवाई अड्डा और हवाई स्टेशन
- टेलीफोन कार्यालय
- प्रसारण केन्द्र
- दूरदर्शन केन्द्र
- अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि बागवानी और नर्सरियां
- गैस/पेट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज
- पार्किंग स्थल, बस स्टाप/शैल्टर, टैक्सी, टांगा और आटो/ रिक्शा स्टैंड
- संभार-तन्त्र हब/कन्टेनर यार्ड, इंग्लैण्ड कन्टेनर डिपो, कन्टेनर माल भाड़ा स्टेशन
- सेक्टर के कुल क्षेत्र के 5% की अधिकतम सीमा तक भाण्डागार।
- धर्मकांटा

V जन उपयोगितायें:

- जल आपूर्ति स्थापना इसमें उपचार संयंत्र भी शामिल हैं
- जल निकास और सफाई स्थापनाएं जिसमें मल निकास उपचार संयंत्र तथा निपटान कार्य शामिल हैं।
- इलैक्ट्रिक पावर प्लांट तथा सबस्टेशन जिसमें ग्रिड सब स्टेशन शामिल है।
- गैस स्थापना तथा गैस वर्कस।

- (v) ठोस कचरा प्रबन्धन स्थल।

VI सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक उपयोग अंचल:

- (i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र, सचिवालय और पुलिस थाना
(ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएँ
(iii) चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थाएँ
(iv) नागरिक/सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाएँ जैसे कि थियेटर, ओपेरा हाऊस इत्यादि जो कि उत्कृष्ट रूप में गैर-वाणिज्यिक किस्म के हों।
(v) रक्षा स्वामित्व वाली भूमि
(vi) ढाबा, रेस्टोरेन्ट निम्नानुसार:

क्रम संख्या	सुविधाओं का नाम	क्षेत्र		सैक्टर में सुविधाओं की संख्या	वाणिज्यिक घटक	अधिकतम भूतल अच्छादन	फर्श क्षेत्र अनुपात
		न्यूनतम	अधिकतम				
1.	ढाबा	500 वर्ग मीटर	1000 वर्ग मीटर	2	50 वर्ग मीटर	50 प्रतिशत	0.50 प्रतिशत
2.	रेस्टोरेन्ट	1000 वर्ग मीटर	2000 वर्ग मीटर	2	10 प्रतिशत	30 प्रतिशत	1.50 प्रतिशत

- (vii) संचार टावर
(viii) कोई अन्य उपयोग जिसका सरकार द्वारा जनहित में निर्णय करें।

VII खुले स्थान:

- (i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा खेल मैदान
(ii) पार्क, हरित पट्टी, बाग तथा अन्य मनोरंजनात्मक उपयोग।
(iii) कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि
(iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ पेट्रोल पम्प, बस पंक्ति/शैल्टर
(v) अनुसूचित सड़कों तथा मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसा कि विद्युत ग्रिड स्टेशन, प्रेषण लाइनें, संचार लाइनें, जल आपूर्ति, सीवरेज लाइनें, ड्रैनेज लाइनें।
(vi) जल निकाय/झील/जल रि-चार्ज जोन
(vii) संचार टावर
(viii) मेला ग्राऊंड, बहुउद्देशीय ग्राऊंड
(ix) कोई अन्य उपयोग, जिसका सरकार लोकहित में निर्णय करें।

VIII कृषि अंचल:

- (i) कृषि, बागवानी, डेरी और मुर्गी पालन
(ii) आबादी देह में गांव घर
(iii) अंचल विनियम XXI में यथा अधिकथित प्रतिबन्धों के अध्याधीन आबादी देह के बाहर फार्म गृह
(iv) मनोरंजन के लिए किसी भाग का वन रोपण विकास

- (v) आबादी देह के समीप विद्यमान गांव का विस्तार यदि यह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या प्रवर्तित परियोजना हो
- (vi) दुग्ध अवशीतन केन्द्र और पैस्चयूरीकरण केन्द्र
- (vii) बस अड्डा और रेलवे स्टेशन
- (viii) अनिवार्य भवनों सहित हवाई अड्डा
- (ix) बेतार केन्द्र
- (x) निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल
- (xi) मौसम कार्यालय
- (xii) भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली केन्द्र और सिंचाई के लिए नलकूप
- (xiii) टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाइनें ओर खम्भे
- (xiv) नियम के अधीन रहते हुए तथा अनुमोदित स्थल पर खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा ईंटों के भट्टे, पत्थर, खदानें और क्रेशिंग शामिल है।
- (xv) शमशान और कब्रिस्तान
- (xvi) गैस/ पेट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज
- (xvii) अक्षय उर्जा तथा गैर अक्षय उर्जा बिजली/संयंत्र
- (xviii) निदेशक के अनुमोदन से एल.पी.जी. भण्डारण गोदाम
- (xix) अन्यथा विनिर्दिष्ट, गैर-प्रदूषण औद्योगिक ईकाइयां होंगी परन्तु समय-समय पर रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के अधीन रक्षा स्थापना के चारों ओर अधिसूचित प्रतिबन्धित पट्टी के बाहर पड़ने वाले स्थल, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए होंगे :-

उद्योग की प्रकृति/किस्म	ग्रामीण उद्योग स्कीम/लघु उद्योग
पहुंच	(i) विद्यमान गांव आबादी देह को घेरने वाली तथा अनुसूचित सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग से भिन्न लोक सड़क/रास्ते से पहुंचयोग्य आधा किलोमीटर पट्टी से अवस्थित। (ii) पहुंच सड़क के साथ 100 मीटर की गहराई तक उपरोक्त (i) में निर्दिष्ट आधा किलोमीटर जोन के बाहर कम से कम 30 फुट चौड़ी लोक सड़क/रास्ते पर (अनुसूचित सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राजमार्ग से भिन्न)
क्षेत्र	कम से कम 2 एकड़

- (xx) प्रतिबन्धित/हरित पट्टी के बाहरी क्षेत्रों से राष्ट्रीय राजमार्ग/अनुसूचित सड़क के साथ-साथ निम्नानुसार ढाबा, रैस्टोरैन्ट, मोटल, रिसॉर्ट तथा मनोरंजन पार्क/थीम पार्क:-

क्रम संख्या	अनुज्ञय क्रिया कलाप	क्षेत्र		वाणिज्यिक घटक	अधिकतम भूतल आच्छादन	फर्श क्षेत्र अनुपात
		न्यूनतम	अधिकतम			
1.	ढाबा	1000 वर्ग मीटर	1 एकड़	50 वर्ग मीटर	40 प्रतिशत	4.0
2	रैस्टोरैन्ट	2000 वर्ग मीटर	1 एकड़	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	1.5

3	बैंकविट सुविधाओं सहित मोटल	2.5 एकड़	5 एकड़	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	1.5
4	रिसोर्ट	4 एकड़	10 एकड़	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	1.5
5	मनोरंजन पार्क/थीम पार्क	2.5 एकड़	10 एकड़	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत	0.5

परन्तु यदि स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो पहुँच अनुमति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त करनी है तथा यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर स्थित है, तो पहुँच अनुमति कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) से प्राप्त करनी होंगी।

(xxi) **बैंकविट हाल:**

अनुज्ञेय अंचल	कृषि
पहुँच	<ol style="list-style-type: none"> 1. पहुँच सड़क की चौड़ाई कम से कम 18 मीटर होनी चाहिए। 2. यदि स्थल अनुसूचित सड़क पर स्थित हो तो इस रास्ते की अनुमति कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) से अपेक्षित है। 3. राष्ट्रीय राजमार्ग से भी पहुँच विचारी जा सकती है, यदि स्थल चौराहा/ पहुँच मार्ग से न्यूनतम दूरी मानक पूरा करते हों तथा न्यूनतम 7 मीटर चौड़ी सेवा सड़क पर अवस्थित हो या आवेदक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पहुँच की पूर्व अनुज्ञा प्रस्तुत करता है।
अपेक्षित क्षेत्र	न्यूनतम : 2.5 एकड़ अधिकतम : 5.00 एकड़
एफ.ए.आर.	0.5 प्रतिशत
भूतल आच्छादन	30 प्रतिशत
परिवर्तन प्रभार	वाणिज्यिक उपयोग के लिए विहित दर का 50 प्रतिशत
एफ.ए.आर. के भीतर अनुषांगिक उपयोगों की अनुज्ञा	उपहार दुकान एस टी डी बूथ खिलौना केन्द्र तथा फूलों की दूकानें इत्यादि के लिए अनुज्ञात एफ.ए.आर. का 10 प्रतिशत
पार्किंग	स्थल क्षेत्र का न्यूनतम 25 प्रतिशत

(xxii) माईक्रोवेव टावर/ स्टेशन/भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र

(xxiii) संचार टावर

(xxiv) सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा नियत परियोजना अनुबन्ध कार्य हेतु अल्पावधि के लिए लगाए जाने वाले तैयार मिश्रण कंक्रीट संयंत्र, वेट मिश्रण संयंत्र, गरम मिश्रण संयंत्र इत्यादि

(xxv) धर्मकांटा

(xxvi) कोई अन्य उपयोग जिसका सरकार लोकहित में निर्णय करें।

IX प्राकृतिक संरक्षण अंचल

(i) कृषि तथा बागवानी

(ii) मत्स्य पालन

(iii) वन रोपण सहित सामाजिक वन/ पौधारोपण

(iv) सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरण समाशोधन प्राप्त करने के बाद क्षेत्रीय मनोरंजनात्मक गतिविधियां

X **बिल्कुल निषिद्ध उपयोग**

उचित लाइसेंस के बिना पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण।

परिशिष्ट-1

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के स्कोप/परिभाषा में सम्मिलित की गई उद्योगों की श्रेणी

(क) कम्प्यूटर डिवाइसिज के अन्तर्गत :

डैस्कटाप

पर्सनल कम्प्यूटरर्स

सरवर्स

वर्क स्टेशन

नोडस

टरमिनलस

नैटवर्क पी.सी.

होम पी.सी.

लैपटॉप कम्प्यूटरर्स

नोट बुक कम्प्यूटरर्स

पामटॉप कम्प्यूटरर्स/पी.डी.ए.

(ख) नैटवर्क कंट्रोलर कार्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :

नैटवर्क इन्टरफेस कार्ड (एन.आई.सी.)

एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./ई.आई.एस.ए./कोम्बो/पी.सी.एम.आई.सी.ए.

एस.आई.एम.एम.मेमोरी

डी.आई.एम.एम.मेमोरी

सैन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट(सी.पी.यू.)

कन्ट्रोलर एस.सी.एस.आई. / ऐरे

प्रोसेसर प्रोसेसर / प्रोसेसर पावर मोडयूल / अपग्रेड

(ग) स्टोरेज यूनिट्स के अन्तर्गत :

हार्ड डिस्क ड्राइव्स/हार्ड ड्राइव्स

आर.ए.आई.डी. डिवाइसिस एवं उसके कन्ट्रोलर

फ्लोपी डिस्क ड्राइव

सी.डी. रोम ड्राइव

टेप ड्राइव्स डी.एल.टी. ड्राइव्स/डी.ए.टी.

ओप्टिकल डिस्क ड्राइव

अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाइज

(घ) अन्य :

की बोर्ड

मोनीटर

माऊस

मल्टीमीडिया किट्स

(ड.) प्रिन्टर एवं आऊटपुट डिवाइसिस के अन्तर्गत :

डोट मैट्रिक्स

लेजरजेट

इन्कजैट

डेस्कजैट

एल.ई.डी. प्रिन्टर्स

लाइन प्रिन्टर्स

प्लॉटर्स

पास बुक प्रिन्टर्स

(च) नेटवर्किंग उत्पाद सहित :

हब्स

रूटर्स

स्विचिस

कोन्सन्ट्रैटर्स

ट्रांसरिसिवर्स

(छ) सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत :

एप्लीकेशन्स सॉफ्टवेयर

आपरेटिंग सिस्टम

मिडल वेयर/फर्म वेयर

(ज) कंप्यूटर सिस्टम के लिए लगने वाला पावर सप्लाय के अन्तर्गत :

स्विच मोड पावर सप्लाय

अनइन्टरप्टिड पावर सप्लाय

(झ) नेटवर्किंग/केबलिंग एवं उससे संबंधित भाग :

(सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित)

फाइबर केबल

कोपर केबल

केबल्स

कनेक्टर्स, टर्मिनल ब्लॉक

जैक पैनेल्स, पैच कोर्ड

माऊटिंग कोर्ड / वायरिंग ब्लॉक

सरफेस माउंट बक्से

(ञ) कन्ज्यूमेबल्स के अन्तर्गत :

सी.डी.रोम/कम्पैक्ट डिस्क

फलोपी डिस्क
 टैप्स डी.ए.टी./डी.एल.टी.
 रिबन्स
 टोनर्स
 इन्कजेट कारटेजिस
 आऊटपुट डिवाइसिस को लगने वाली इंक

(ट) **इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट :**

प्रिंटेड सर्किट बोर्ड/पापुलेटिड पी.सी.बी.
 प्रिंटेड सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी.
 ट्रांजिस्टर्स
 इन्टैग्रेटेड सर्किट्स/आई.सी.एस.
 डायोड्स/थार्डिस्टर्स/एल.ई.डी.
 रेसिस्टर्स
 केपेसिटर्स
 स्विचिस (आन/आफ, पुश बटन्स, रोकर्स इत्यादि)
 प्लगस/सोकेट्स/रिलेज
 मेगनेटिक हेड्स, प्रिन्ट हेड्स
 कनेक्टर
 माइक्रोफोन्स/स्पीकर्स
 फ्यूजिस

(ठ) **टैलीकम्यूनिकेशन इक्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :**

टैलीफोन
 विडियो फोन
 फेसी माईल मशीन/फैक्स कार्ड
 टैली प्रिन्टर/टैलेक्स मशीन
 पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स. टैलीफोन एक्सचेंज
 मल्टीप्लेक्सर्स/म्यूजिस
 मोडम्स
 टैलीफोन आन्सरिंग मशीन
 टैलीकम्यूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स
 एन्टेना एवं मास्ट
 वायरलैस डेटाकोम इक्वीपमेन्ट
 रिसीविंग इक्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाइल/सैल्यूलर फोन इत्यादि
 वी.एस.ए.टीज.
 • वीडियो कानफेरेंसिंग इक्वीपमेन्ट

वीडियो और डिजिटल सिंगनलिंग दोनों के लिए लगने वाले सैट टाप बक्से के अन्तर्गत।

(ड) सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक क्रिया और सेवायें हैं जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवायें जिनको :

- भारत से बाहर वितरित करने के लिए
- संचार-जाल के लिए वितरित करने के लिए; या
- या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्रोत) या उस कम्पनी के सुदूर गौण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर स्थित)

टिप्पण :-

जो सेवाएं इनमें शामिल नहीं हैं, वह :—

(iii) सुदूर उत्पादन/निर्माण इकाइयां

(iv) कम्पनियों के संचालित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं

(v) इन्टरनेट पर वास्तविक व्यवसाय

निम्नलिखित सेवाएं उपरोक्त दिये गये मापदण्ड यदि पूर्ण करते हैं तो उन्हें सम्मिलित किया जायेगा :

(i) बैंक ऑफिस आप्रेशनस

(ii) काल सैन्टरज़

(iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन

(iv) डाटा प्रोसैसिंग

(v) अभियान्त्रिकी तथा रचना

(vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिज

(vii) मानव संसाधन सेवायें

(viii) बीमा दाता निपटान क्रम

(ix) लीगल डाटा बेस

(x) मैडीकल ट्रान्सक्रिप्शन

(xi) पे-रोल

(xii) सुदूर रख-रखाव

(xiii) राजस्व लेखे

(xiv) स्पोर्ट सैन्टरज़; तथा

(xv) वैब-साइट सर्विसेज ।

पी० राघवेन्द्र राव,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 5th November, 2015

No. CCP(NCR)/ DDP(MBIR)/2015/3070.—In exercise of the powers conferred by Sub-section 4 of Section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Act 41 of 1963), and in supersession of Haryana Government, Town and Country Planning Department, Notification No. CCP(NCR)/DDP(Bawal)/2007/4244 dated 5th December, 2007 published in Haryana Government Gazette on 5th December, 2007 and all other notifications issued in this behalf, the Governor of Haryana hereby publishes the Draft Development Plan, Manesar–Bawal Investment Region (MBIR)–2039 A.D. along with restrictions and conditions as given in the Annexure A and B proposed to be made applicable to the controlled areas specified in Annexure B.

Notice is hereby given that the Draft Development Plan shall be taken into consideration by the Government after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Director, Town and Country Planning, Haryana, SCO-71-75, 2nd Floor, Sector – 17, Chandigarh, from any person in writing in respect of this plan before the expiry of the period so specified.

DRAWINGS

1. Existing Land use Plan drawing No. DTP(RE)490/2007 dated the 27th August, 2007 prepared for Controlled Area No. I, II and III Around Municipal Limit of Bawal and Additional Controlled Area No. II Around Municipal Limit of Rewari (already notified *vide* Haryana Government, Town and Country Planning Department notification No. CCP(NCR)/DDP(Bawal)/2007/4244 dated the 5th December, 2007 published in Government Gazette on 5th December, 2007).
2. Existing Land Use Plan Drawing No. DTP(RE)638/2013 dated the 24.12.2013/04.11.2015 prepared for Controlled Area No. II Around Municipal Town, Rewari and Controlled Area Around Primary School, Village Khaliawas.
3. Existing Land Use Plan for Additional Controlled Area-IV Around Municipal Town Bawal Drawing No. DTP (RE)635/2013 dated 16.12-2013/19.08.2014/04.11.2015.
4. Part existing Land Use Plan for Controlled Area-III Around Municipal Town Rewari Drawing No. DTP(RE) 659/ 2014 dated 20.11.2014/04.11.2015.
5. Existing Land Use Plan for Controlled Area-V Around Municipal Town Bawal Drawing No. DTP (RE) 636/2013 dated 16.12.2013/19.08.2014/04.11.2015.
6. Existing Land Use Plan for Controlled Area-II Around Municipal Town Dharuhera Drawing No.DTP(RE) 637/2013 dated 16.12.2013/19.08.2014/04.11.2015.
7. Draft Development Plan Manesar-Bawal Investment Region-2039AD Drawing No. DTP(RE) 632/2013 dated the 22.10.2013/04.11.2015.

ANNEXURE 'A'

**EXPLANATORY NOTE ON THE DRAFT DEVELOPMENT PLAN 2039 AD FOR THE CONTROLLED
AREAS OF MANESAR BAWAL INVESTMENT REGION (MBIR), DISTRICT
REWARI**

INTRODUCTION:

It is the vision of Government of India (GoI) to develop an extended industrial corridor between Delhi and Mumbai; a band of 150 km along the alignment of Western Dedicated Freight Corridor (DFC) called Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC). This envisages promotion of industrial development with high quality physical and social infrastructure. The DMIC Development Corporation Limited (DMICDC; Special purpose Vehicle) has been created under Ministry of Commerce (MoCom), GoI, to have a planned and coordinated Development of DMIC region.

The Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation (HSIIDC); Public Limited Company wholly owned by the Government of Haryana, is the nodal agency for DMIC MBIR project for state of Haryana. Jurong Lead Consortium (Consultant) is mandated to undertake the consultancy services for preparation of Development Plan (DP) for Manesar – Bawal Investment Region (MBIR) of Haryana Sub Region of DMIC. The Manesar Bawal Investment Region (MBIR) is proposed as a major new industrial hub to be located in Rewari District of Haryana.

The MBIR is the first investment region to be designated under the proposed Delhi – Mumbai Industrial Corridor project (DMIC), an initiative to create a linear zone of development along a Dedicated Freight Corridor (DFC) railway line.

LOCATION AND LINKAGES:

Delineated MBIR is positioned within Rewari District of Haryana. It is located at 82 KM milestone in the south – west direction of the National Capital Territory (NCT) of Delhi. The geographical position of the district is 27°57' N to 28°27' N latitude and 76°17' E to 76°51' E longitudes. Its geographical boundaries have Jhajjar District in its North, Mahendergarh District in its West and Gurgaon district in its East and North – East directions. Alwar District of Rajasthan district touches Rewari in the South – East. District Rewari is well connected through network of National Highways, State Highways and Railways to all major nodes within Haryana, NCR, Punjab, Rajasthan district and rest of India. The total length of roads is 860 km and all the villages are connected with pucca roads. Rewari District is among the high density railway network districts in India Rewari Railway station (Junction) is the confluence of / merging point of six railway lines viz a viz) Delhi – Rewari – Alwar – Jaipur / Mathura, (b) Delhi – Rewari – Narnaul – Jaipur, (c) Rewari – Mahendergarh – Loharu – Bikaner, (e) Rewari Bhiwani – Hissar and (f) Rewari – Jhajjar – Rohtak line.

The Greenfield alignment of Dedicated Freight Corridors (DFC) passes through Rewari District connecting all existing and under construction railway links. DFC junction station is proposed to be developed near Rewari City along with Mega Logistic Park. Indira Gandhi International Airport, New Delhi is 80 KM away from Rewari City and Jaipur Airport is 209 KM away.

CLIMATE

Generally 'bright sunshine' scarcity and 'variability of rainfall' and a high rate of evaporation are the dominant climatic factors in Rewari. The climate of Rewari District can be classified as tropical steppe; semi – arid and hot *i.e.* mainly dry with very hot summer and cold winter, except for monsoon period when moist air from oceanic origin penetrates into the district.

- (a) **Temperature:** The climate is hot and semi – arid with extremes of temperature in summer and winter. The mean minimum and maximum temperature in the area ranges from 5.6° C to 41° C during January and May/June respectively.
- (b) **Rainfall:** The normal monsoon and annual rainfall in the district is 489 mm and 553 mm, respectively, which is unevenly distributed over the area.
- (c) **Relative Humidity:** The relative humidity is lower than 30 % during months of April till June and is higher than 70 % in the monsoon months.
- (d) **Wind Direction:** The full data for Rewari indicates that the overall predominant wind direction is from the West (54%) during the summer season. However the annual pattern shows that the predominant combined wind direction is from West and North – West.

GEOLOGY AND NATURAL HAZARDS

The lithology of Rewari District can be divided into two broad parts, namely; (a) hard rocks, (b) unconsolidated sediments of both Aeolian and fluvial origin.

- (a) **Relief and Slope:** In general the maximum relief in the district is observed at the residual structural hills where the general elevation is 300 m above mean sea level. The overall slope of the land comprising the alluvial plains is gently towards North. The south-western side of the MBIR towards the boundary of the Rajasthan shows some rocky outcrops which are approximately 300 m high. The Sahibi River flows in the northern portion of the MBIR.
- (b) **Ground Water:** Ground water in the district occurs under unconfined, semi-confined and confined conditions and is tapped by the dug well, shallow tube well and deep tube well respectively. The ground water quality in most part of the MBIR is sub-marginally saline with a small patch of marginally saline on NH-48. Further fresh water is found along Sahibi River on southern side of MBIR. The net ground water resource of Rewari District have been estimated to be 260.65 million cubic meter (MCM) and the gross ground water draft of the district is 313.91 MCM leaving behind a shortfall of (-) 54.68 MCM. Central Ground Water Authority has notified Khol Block for regulation of ground water development.
- (c) **Soil Quality:** The district forms a part of Indo- Gangetic plains. The soil – texture of the district varies from sandy to loamy sand. The district has around 90 % soils under loamy sand texture. Being coarse textured, the soils are poor in water as well as in nutrient retention.

FOREST AND NATURAL FEATURES:

The Rewari District and consequently the MBIR, falls under semi-arid Punjab plains in terms of Bio-geographic provinces. Majority forest in the district belongs to sub-tropical thorny forest. In district the tree cover is more in non – forest areas than in the natural forest areas. As per State Forest Report, 2005 of the Forest Survey of India, the total forest cover is 2.64 percent of the total geographical area.

Three major natural features were identified within the delineated region. These are (i) Sahibi River, (ii) Aravalli Hills and (iii) Forest Areas. Further, dense plantations in form of kikars is observed in this area. The area under Aravalli hills is around 13.5 sq. kms. whereas the forest area cover only 1.4 sq. km. However, the area under kikars is considerable and measures 17.74 sq. km. Thus, a total area of 32.64 Sq. km is under natural features (excluding River Sahibi).

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR

The Government of India has announced establishment of Dedicated Freight Corridor (DFC) between Delhi and Mumbai (DFC Western), covering an overall length of 1483 km, which passes and passing through the States of U.P., NCT of Delhi, Haryana, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra, with end terminals at Dadri in the National Capital Region (NCR) of Delhi and Jawahar Lal Nehru port near Mumbai. This DFC offers high-speed connectivity for high axle load wagons (25 tonnes) of double stacked container trains supported by high power locomotives. The western DFC is expected to become operational in 2016-17.

DEVELOPMENT PLAN PROVISIONS:

The MBIR delineated site is a larger extension of existing Bawal industrial area and Bawal town covering 140 villages and admeasuring to 402.20 sq. km. with combined existing population of 2,20,048 as per census 2011.

The Plan is designed to accommodate industrial and population growth till 2039 AD in a phased manner. It provides for large contiguous industrial areas along with residential areas to accommodate 33.15 million people. It is estimated that around 7,36,666 say 7,40,000 dwelling units would be required with average household size of 4.5 persons. Hence, according as per average household size of 4.5 persons, the population would be 33.15 lacs.

LAND USE DISTRIBUTION

The plan is designed to accommodate the projected land demand for base industrial activities, employment and population together with the residential, commercial and other land uses necessary to sustain a modern city. The total area of the Development Plan comprising of 9 controlled areas is about 40220 hectares. The break-up of this area under broad categories is as under:

Sr. No.	Category	Area (in hectares)
1	Proposed Urbanizable Area	26737
2	Agriculture Zone	7935
3	Existing Settlements	1654
4	Existing Industrial Estate	1081
5	Natural Conservation Zone	2813
	Total	40220

The urbanizable zone has been further divided under different land uses, with following area statement:

Area Statement of Land Uses of Urbanisable Zone

Sr. No.	Land Use	Area (in hectares)	%
1	Residential	9724	36.37
2	Commercial	1149	4.30
3	Industrial	5247	19.62
4	Transport and Communication	4266	15.96
5	Public Utilities	396	1.48
6	Public and Semi-public	944	3.53
7	Open Spaces	5011	18.74
	Total	26737	100.00

(a) Residential Use:

An area of 9724 hectares has been earmarked for residential purpose to accommodate 33.15 lacs projected population with average residential density of 341 PPH. It is proposed that the aforesaid residential areas be developed by public and private sectors as well as on PPP mode. The residential areas are proposed to be developed on neighbourhood concept by making provision of all community facilities and services within the sectors as per sector density. The density ranges from less than 30 dwelling units per hectare at the lowest end to more than 100 dwelling units per hectare at its highest end. Three categories of residential density has been proposed viz (a) Low Density-150 PPH, (b) Medium Density-300 PPH and (c) High Density-450 PPH. The residential land use distribution is guided by the thematic concept of resort living, urban living and innovative living. The Central Business District (CBD) as well as the regional centre as part of the urban living constitute of high density residential development. The medium density residential areas are concentrated along the belt between SH 15 and V-2 road towards the South-West part of Manesar Bawal Investment Region. The low density residential area is highly concentrated in the North West region along hill area. This residential area shall be developed on the concept of resort living with developments like bungalows, detached and semi – detached housing. Another parcel of low density residential area is located in the southern part of the Manesar Bawal Investment Region supporting the research and development institutes. In order to improve the living environment of the sector, the following specific proposals are made in the plan:

- (a) 10 town parks each measuring four hectares have been proposed, which have been well distributed all over the plan.
- (b) The minimum area for parks/open spaces in a residential colony/sector shall be planned in such a manner that it shall meet the minimum norm of 2.5 square meters per person.
- (c) The minimum width of the roads in a residential colony/sector shall not be less than 12 meters.

(b) Commercial Use:

An Area of 1149 hectares has been reserved for commercial use. In order to ensure efficient functioning of the investment region and to meet the needs of a projected population of 33.15 million by 2039 AD, a hierarchy of commercial centres has been proposed ranging from Central Business District, Regional

Centre, Town Centre to Neighbourhood Centre. The CBD shall be located in commercial sectors C-13 to C-16, the Regional Centre in commercial Sectors C-1 to C-6, Sub-Regional Centre in Sectors C-20 to C-23 whereas town/ neighbourhood centres shall be located at the time of preparation of layout plans of individual sectors.

The main focus of commercial/ financial activity shall be in CBD and the two regional centres. The CBD will be developed as a world class business district in the South – West region along NH-48 . The objective is to create an iconic development which will serve as the new landmark for the entire investment region.

The Regional Centre in the North – East part along NH-48 shall be a major commercial/ institutional hub. While the Regional Centre along SH-15 will cater more towards high end retail and entertainment uses.

(c) Industrial Use:

The Industrial sector is projected to create employment for approximately 1.6 million and require additional 5247 hectares apart from the existing industrial estate for development of Industries by 2039 A.D. For long-term planning and projection purposes, the demand for industrial land is classified broadly under the categories like; Business parks, Standard / Flatted Factories, Allocated lots and Special industries.

The location of the proposed industrial area has been given in the sectors adjoining existing Bawal Industrial Estate and proposed Logistic Hub to ensure speedy movement of goods. The planning takes into consideration the environmental impact and neighboring settlements. A 80 metre road and total 300 meter green buffer separates the industrial area from the residential sectors. Clean / Green industries and business parks are proposed to be located within new township, to make live-work-play kind of development. Further, there shall be proper disposal of waste water from industries and extraction of ground water for industrial purpose shall not be allowed.

(d) Transport and Communication:

The Development Plan is based on multi-model transport strategy covering both public and private transport. A good system of roads, footpaths and cycle – tracks, and public transport system matching the transport demand are proposed to be developed. An area of 4266 hectares has been earmarked towards transport and communication to provide for roads, ISBTs, Bus depots/ station, helipad, railway line, DFC and logistics facilities like Integrated Multimodal Logistic Hub (IMLH), ware houses, agriculture mandies etc.

The road network derives its form from existing & planned road network of Rewari, Dharuhera and Bawal Development Plans as well as the concept of grid network. The plan is designed with a network of urban roads (Arterial, Sub – Arterial and Collector roads) plus a host of roads of regional and national importance (NH & SH) whose widths and ROWs have been standardized.

The total length of urban roads within MBIR is around 547 km; includes NHs/ SHs/ outer ring road. Land reservation for major roads and lane configuration for MBIR road network is as below:

Land Reservation for Development Plan roads

Sr. No.	Classification	Land Reservations	Remarks
Arterial Roads			
I	VN1	60 meters wide with 60 meters green belt on both sides	National Highway -48
II	VN2	Existing width with 50 meters green belt on both sides	National Highway -71
III	VS	60 meter wide with 30 meters green belt on both sides	State Highway
IV	VB	100 meters with 100 meters green belt on both sides	Entire Route to have BRT, Bawal Peripheral road
V	V1	80 meter wide with 50 meter green belt on both sides	Including MBIR peripheral Road

VI	VI (A)	80 meter wide with 50 meter green belt on both sides	Entire Route to have BRT
VII	V2	60 meter wide with 50 meter green belt on both sides	
VIII	V2 (A)	60 meter wide with 50 meter green belt on both sides	Entire Route to have BRT
IX	V2 (B)	60 meter wide with 30 meter green belt on both sides	Entire Route to have BRT
Sub-Arterial Roads			
X	V2 (C)	60 meter wide	
XI	V2 (D)	60 meter wide	Entire Route to have BRT
XII	V3	45 meter wide with 30 meter green belt on both sides	
XII	V3 (A)	45 meter wide	

Lane configuration for MBIR Road Network

Sr. No.	Road Category	Assigned lane configuration
I	Arterial Road	8/6 lane divided carriageway with service lanes, footpaths & non – motorized lanes on both sides
II	Sub – Arterial	4 lane divided carriageway with service lanes, footpaths & non – motorized lanes on both sides
III	Bawal peripheral (Inner) Ring Road	6 lane divided carriageway with service lanes, footpaths & non – motorized lanes on both sides
IV	MBIR Peripheral (Outer) Ring Road	6 lane divided carriageway with service lanes, footpaths & non – motorized lanes on both sides
V	National Highways	8 lane divided carriageway with service lanes, footpaths & non – motorized lanes on both sides
VI	State Highway	4 lane divided carriageway with service lanes, footpaths & non – motorized lanes on both sides

Looking at the ground situation, where a flyover being developed at the junction Garhi Bolni-Kasim Road and with NH-48 and DFC runs parallel to the junction and the proposed Integrated Multimodal Logistic Hub (IMLH), the alignment of Bawal peripheral road has been modified to take the advantage of flyover and at the same time provide connectivity to IMLH.

The width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies. Wherever, roads shown in the Development Plan are found to be non-feasible, as per ground condition, Government shall be competent to realign/delete the same after recording the reasons thereof.

Similar to Bawal peripheral road, 58 km long MBIR peripheral road, (80 mtr. wide with 50 mtr. green belt on both sides) is provided which would collect and distribute the traffic from and on major NHs & SHs without disturbing the internal traffic movements.

All major roads are planned to be signal free roads with flyovers, clover leaf interchanges and railway over bridges at several locations. For smooth & safe pedestrian cross -over foot- over bridges have been planned on all roads except roads falling under industrial area. Approx. 1000 foot over bridges (every 500 m) would be required on planned urban roads within MBIR. All 49 interchanges would be signal free and are proposed with flyovers (19), clover - leaf interchanges (16) & RUBs.

Given the projected / estimated ridership, BRT corridors are proposed to be developed on the selected arterial & sub arterial roads. Around 18 % of planned urban roads would have BRTS system. The

total length of BRT corridor is around 100 km. The Development Plan provides for one Bus Depot for fleet size of 200 / 250 buses on an area measuring 12 acres and 15 bus terminals each measuring 4 acres.

- **Integrated Passenger Hub:** This would comprise of ISBT, bus depot & passenger/ bus terminal and workshop and interconnection with MRTS.
- **Passenger Hub:** this would comprise of bus depot and bus terminal.
- **Bus Terminals:** this is primarily a local bus station.

The Development Plan provides for 5 hectares of land for development of a Heliport within MBIR. The MBIR Plan comprises of four types of railway system *i.e.* Indian Railway, (b) Proposed Dedicated Freight Corridor, (c) Proposed Gurgaon – Bawal MRTS and (d) Proposed New Delhi – Alwar Regional Rapid Transit System.

(e) Public Utilities:

An area of approximately 396 hectares of land has been proposed for Public Utilities like water supply system, sewerage system, drainage, solid waste disposal system, etc. Public Utilities have been located based on their demand and proximity to end user.

Massani barrage is proposed to be redeveloped with floodgates etc. and shall be used as main water storage reservoir with an increased capacity to meet three months water demands of MBIR. There shall be planned drainage system, within ROW of roads and sufficient cross drainage structure, for smoother and faster evacuation of rainwater/floods waters. Further, there shall be total safe yield of ground water over entire MBIR are not to exceed 45 MLD, which shall be strictly monitored by the competent authority. The existing drinking water supply schemes shall remain continued and the MBIR will have its own water supply infrastructure. Further, industrial water supply scheme shall be augmented to cater to the industrial water demand for existing and upcoming expansion of Bawal industrial area. In addition, the effort shall be made for use of the existing ponds for water storages and recharge structures.

(f) Public and Semi-Public:

In order to cater the institutional demand of 33.15 lacs population, an area of 944 hectares of land has been proposed for public and semi public uses in the plan. Its distribution takes into account the best location for different types of public and semi public uses within the MBIR. Public / Semi – public uses have been positioned with an objective to integrate it with the residential areas. This will reduce trip length and improve quality of life of the residents. The major public uses nodes are located within the CBD and Regional Centers. Other public and semi public uses are located within close vicinity of commercial centers. Major public and semi public hubs are located at NH-48, V-2 road, and other arterial roads .

(g) Open Space:

An area measuring 5011 hectares has been provided under open space. The allocation and distribution of open space is as follows:

1. Parks & Sports Facilities along Sahibi River & Massani Barrage.
2. Recreation and sports activities including golf courses along Sahibi River.
3. Three very large Regional Parks at City level.
4. 300 meter (250+50 metres) green belt between industrial & Residential Use.
5. Green belt provided along the major roads.
6. The cycle paths and walkways have been provided in the green buffers.

AGRICULTURAL ZONE

A sizeable area has been reserved as agricultural zone along Rajasthan Border. This zone however will not eliminate the essential building development within this area such as the extension of existing villages but contiguous to abadi area, if undertaken under a project approved or sponsored by Government and other ancillary and allied facilities necessary for the maintenance and improvement of the area as an agricultural area.

NATURAL CONSERVATION ZONE

The Aravalli Ranges have been designated as Natural Conservation Zone in the Plan in accordance with Regional Plan-2021, except those areas which are coming in the urbanisable area. A total area measuring 2813

hectares has been earmarked for this zone, wherein the activities like; Agriculture, horticulture, pisciculture, social forestry, afforestation and regional recreational activities after obtaining environmental clearance from the competent authority shall be permissible. Under Natural Conservation Zone activities to be provided mentioned as per approved Revised Regional Plan 2021 AD/Sub Regional Plan 2021 AD of Haryana Sub Regional of NCR.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

For protection of Aravallis, the notification of Ministry of Environment & Forest (MOEF), Government of India dated 07.05.1992, shall be applicable. Similarly, for execution of any project, the project proponent will have to obtain environmental clearance in terms of notification dated 14.09.2006, which is mandatory in nature. In addition, the areas notified under Section 4 and / or 5 of Punjab Land Preservation Act, 1900 and areas covered under Aravalli plantation are also shown as 'forest' in view of the orders of the Hon'ble Supreme Court, in which no urbanization shall be allowed. Similarly, the restrictions for protection of environment in any manner shall also be followed and implemented. Notifications issued by MoEF, Government of India, from time to time shall be applicable and binding.

CONSERVATION OF HERITAGE SITES

The monuments, heritage sites, special areas of aesthetic, sentimental or historic value which require protection shall be protected.

ZONING REGULATION:

The legal sanctity to the proposals regarding land use is being given effect by a set of zoning regulations (Annexure B) which form part of this development plan. These regulations will govern the change of land use and standards of development. They will also elaborately detail out allied and ancillary uses which will be permitted in the various major land uses and stipulate that all change of land use and development shall be in accordance with the details shown in the sector plan thereby ensuring preparation of detailed sector plans for each sector to guide the development and enforce proper control.

ANNEXURE-B

ZONING REGULATIONS:

Governing use and development of land in the controlled areas of covered by the Development Plan of Manesar Bawal Investment Region published under Section 5 shall be as shown in drawing No. DTP(RE)632/2013 dated 22.10.2013/04.11.2015.

I. General:

- (1) These Zoning regulations, forming part of the Draft Development Plan Manesar-Bawal Investment Region 2039 AD shall be called zoning regulations of the Draft Development Plan Manesar Bawal Investment Region 2039 AD.
- (2) The requirements of these regulations shall extend to the whole of the area covered by the Draft Development Plan and shall be in addition to the requirements of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Act 41 of 1963) and the rules framed there under :

II. Definitions:

In these Regulations unless the context otherwise requires:-

- (i) '**Agro Based Industries**' means an industrial unit, which uses food grains, fruits or agro waste as a raw material;
- (ii) '**Approved**' means approved under the Act and Rules framed thereunder;
- (iii) '**Building Rules**' means the Rules contained in Part-VII of the Rules;
- (iv) '**Cyber City**' means self contained intelligent city with high quality of infrastructure, attractive surrounding and high speed communication access to be developed for nucleating the Information Technology concept and germination of medium and large software companies/Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing units may be allowed;
- (v) '**Cyber Park/Information Technology Park**' means an area developed exclusively for locating software development activities and Information Technology Enabled Services wherein no manufacturing of any kind (including assembling activities) shall be permitted;
- (vi) '**Drawing**' means the drawing no. DTP(RE) 632/2013 dated the 22.10.2013/04.11.2015;

- (vii) **'Extensive Industry'** means an industry setup with the permission of the Government and in extensive employing more than 100 workers and may use any kind of captive power of fuel provided they do not have any obnoxious features;
- (viii) **'Farm House'** means a house constructed by the owner of a Farm at his land for the purpose of:-
 (a) Dwelling unit i.e. main use.
 (b) Farm shed i.e. Ancillary use.

Notes:-

- (1) The construction of the farm house shall be governed by the restrictions given under clause XXI regarding "Provision of Farm House outside abadi-deh in Agriculture Zone";
- (2) The farm sheds regarding building control and site specifications shall be governed by the restrictions mentioned in clause XXI;
- (ix) **'Green Belt'** shall mean a strip of land along sector/arterial road or as a buffer between incompatible uses shown in the development plan and is primarily meant for widening of the sector/arterial roads or as a buffer to check pollution like noise, smoke, dust harmful particles etc.
- (x) **'Floor Area Ratio (FAR)'** means the ratio between the total floor area of a building on all floors and the total area of the site;
- (xi) **'Group Housing'** shall be the buildings designated in the form of flatted development for residential purpose or any ancillary or appurtenant building including community facilities, public amenities, public utility and shopping area as may be prescribed and approved by the Director, Town and Country Planning, Haryana;
- (xii) **'Heavy Industry'** means an industry to be set up in public or semi-public or private sector with the permission of the Government (the cost of plant, machinery etc. as defined in the industrial policy of the Government);
- (xiii) **'Information Technology Industrial Units'** means the categories of industries included in the Annexure of the Government of Haryana Information Technology Policy, 2000 and as may be defined by the Government of Haryana from time to time;
- (xiv) **'Ledge or Tand'** means a shelf-like projection, supported in any manner whatsoever, except by means of vertical supports within a room itself but not having projection wider than one metre;
- (xv) **'Light Industry'** means an industry not likely to cause injurious or obnoxious noise, smoke, gas, fumes, odours, dust, effluent and any other nuisance to an excessive degree and motivated by electric power;
- (xvi) **'Local Service Industry'** means an industry, the manufacture and product of which is generally consumed within the local area, e.g. bakeries, ice-cream manufacturing, aerated water, atta chakkies with power, laundry, dry-cleaning and dyeing, repair and service of automobile, scooters and cycles, repair of household utensils, shoe-making and repairing, fuel depot etc. provided no solid fuel is used by them;
- (xvii) **'Loft'** means an intermediary floor on a residual space in a pitched roof, above normal floor level with a maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes;
- (xviii) **'Material Date'** means the date of publication of notification of following controlled areas :

Sr. No.	Name of Controlled area	Material date
1	Additional Controlled Area – II around municipal town, Rewari declared <i>vide</i> notification No. CCP (NCR) RWR (ACA-II)/A/2007/424 dated 09.02.2007 and published in Haryana Government Gazette dated the 9th February, 2007.	9th Feb 2007
2	Controlled areas of Bawal declared <i>vide</i> notification No. PC-97/191 dated 12th March, 1997 published in Haryana Government Gazette dated 8th April, 1997.	8th April, 1997
3	Additional Controlled areas –II& III of Bawal declared <i>vide</i> notification No. CCP(NCR)/Bawal/ACA-II, III/2007/1622 dated 20th April, 2007 published in Haryana Government Gazette dated 20th April 2007.	20th April, 2007
4	Controlled Area Around Primary School Khaliawas notified <i>vide</i> notification No. CCP (NCR) RWR/KWS/CA (B)/ 2007/ 425 dated 09.02.2007	9th Feb, 2007
5	Additional Controlled Area – IV around Municipal Town Bawal notified <i>vide</i> notification No. CCP (NCR) –RE- BWL(ACA-IV)/2013/244 dated 23.01.2013	23th Jan, 2013

6	Controlled Area –II Around Municipal Town Dharuhera notified <i>vide</i> notification No. CCP (NCR) RE- MBIR/CA-II/2013/245 dated 23.01.2013	23th Jan, 2013
7	Controlled Area –V around Municipal Town Bawal notified <i>vide</i> notification No. CCP (NCR) RE-MBIR/ C-V/2013/ 246 dated 23.01.2013	23th Jan, 2013
8	Controlled Area –III Around Municipal Town Rewari notified <i>vide</i> notification No. CCP (NCR) RE-MBIR/ CA-III/2013/ 247 dated 23.01.2013	23th Jan, 2013
9	Controlled Area – IV around Municipal Town Rewari notified <i>vide</i> notification No. CCP (NCR) RE-MBIR/ CA-IV/2013 /248 dated 23.01.2013	23th Jan, 2013

- (xix) **‘Medium Industry’** means all industries other than ‘Light Industry’ and ‘Local Service Industry’ and not emitting obnoxious or injurious fumes and odours;
- (xx) **‘Non-conforming use’** in respect of any land or building in a controlled area means the existing use of such land or building which is contrary to the major land use specified for that part of the area in the development plan;
- (xxi) **‘Obnoxious or Hazardous Industry’** means an industry set up with the permission of the Government and is highly capital intensive associated with such features as excessive smoke, noise, vibration, stench unpleasant or injurious effluent, explosive, inflammable material etc. and other hazards to the health and safety of the community;
- (xxii) **‘Public Utility Service Building’** means any building required for running of public utility services such as water-supply, drainage, electricity, telephone, post and transport and for any municipal services including a fire station;
- (xxiii) **‘Rules’** means the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965;
- (xxiv) **‘Rural Industries Schemes’** means industrial unit, which is registered under rural industries schemes by the Industries Department;
- (xxv) **‘Sector Area’** and **‘Colony Area’** means the area of sector or of the colony as shown on the drawing:-

Explanation:

- (1) In this definition, the ‘Sector Area’ or ‘Colony Area’ shall mean the area of the Sector or of Colony as shown on the drawing or on the approved layout plan of the Colony/Sector which will be excluding the area unfit for building development within the sector or the colony as the case may be;
- (2) In the layout plan of Colony or Sector, other than industrial Colony/Sector, the land reserved for roads, open space, schools, public and community building and other common uses shall not be less than 45 percent of the gross area of the land under the Colony/Sector;
- (xxvi) **‘Sector Density’** and **‘Colony Density’** shall mean the number of persons per hectare in sector area or colony area, as the case may be;

Explanation:

For the purpose of calculation of sector density or colony density, it shall be assumed that 55 percent of the sector area or colony area will be available for residential plots including the area under Group Housing and that every building plot shall on the average contain three dwelling units each with a population of 4.5 persons per dwelling unit or 13.5 persons per building plot or as incorporated in the zoning plan of the colony/group housing complex. In the case of shop-cum-residential plot, however, only one dwelling unit shall be assumed.

- (xxvii) **‘Site Coverage’** means ratio expressed in percentage between the area covered by the ground floor of building and the area of the site;
- (xxviii) **‘Small Scale Industry’** means industrial unit, which is registered as small scale industry by the Industries Department;
- (xxix) **‘Subservient to Agriculture’** means development and activities, which are required to assist in carrying out the process of agriculture such as tubewells, pump chambers, wind mills, irrigation drains, pucca platforms, fencing and boundary walls not more than 4 feet high and with maximum 3 feet high fencing, water hydrant etc.;

- (xxx) The terms '*Act*', '*Colony*', '*Coloniser*', '*Development Plan*', '*Sector*' and '*Sector Plan*' shall have the same meaning as assigned to them in Punjab Scheduled Road and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and rules, 1965;
- (xxxi) '*Town Density*' means number of persons per hectare in the town;
- (xxxii) '*Urbanisable Limit*' means the limit covering the urbanisable area proposed for development by defining the land uses of sector and which includes the periphery roads and the green belts;
- (xxxiii) Any other term shall have the same meaning as assigned to it in the Act and Rules.

III. Major Land Uses/Zone:

- (1) (i) Residential Zone
(ii) Commercial Zone
(iii) Industrial Zone
(iv) Transport and Communication Zone
(v) Public Utility Zone
(vi) Public and Semi Public Zone
(vii) Open Spaces Zone
(viii) Agriculture Zone
(ix) Natural Conservation Zone.
- (2) Classification of major land uses is according to 'Appendix A' sub-joined to these zoning regulations.

IV. Division into Sectors:

Major land uses mentioned at serial Nos. (i) to (vii) in zoning regulation-III above, which are land uses for building purposes, have been divided into sectors as shown on the concerned development plan drawing, and each sector shall be designated by the number as indicated on the drawing.

V. Detailed land uses within major uses:

Main, ancillary and allied uses, which are subject to the other requirements of these regulations and of the rules may be permitted in the respective major land uses zones are listed in 'Appendix B' sub-joined to these zoning regulations.

VI. Sectors not ripe for development:

Notwithstanding the reservation of various sectors for respective land uses for building purposes, the Director may not permit any changes in their land use or allow construction of building thereon from consideration of compact and economical development of the controlled area till such time as availability of water supply, drainage arrangement and other facilities for these sectors are ensured to his satisfaction.

VII. Commercial Sectors and belts/strips to be developed exclusively through Government Enterprises:

- (1) For the development of the sectors and belts/strips reserved for commercial use, private developers shall be permitted to develop to the extent of 10% of the sector area as per the layout plan approved by competent authority, after obtaining license under Act No. 8 of 1975. Balance 90% area shall be developed exclusively by the Government or a Government undertaking or by a public authority approved by the Government.
- (2) Notwithstanding the provision of clause (1) above, the Government may reserve at any time, any other sector for development exclusively by it or its agencies indicated above.

VIII. Land Reservations for Major Roads:-

- (1) Land reservation for major roads marked in the Drawing shall be as under:-

Sr. No.	Classification	Land Reservations	Remarks
Arterial Roads			
I	VN1	60 meters wide with 60 meters green belt on both sides	National Highway -48
II	VN2	Existing width with 50 meters green belt on both sides	National Highway -71

III	VS	60 meter wide with 30 meters green belt on both sides	State Highway
IV	VB	100 meters with 100 meters green belt on both sides	Entire Route to have BRT, Bawal Peripheral Road
V	V1	80 meter wide with 50 meter green belt on both sides	Including MBIR Peripheral Road
VI	VI (A)	80 meter wide with 50 meter green belt on both sides	Entire Route to have BRT
VII	V2	60 meter wide with 50 meter green belt on both sides	
VIII	V2 (A)	60 meter wide with 50 meter green belt on both sides	Entire Route to have BRT
IX	V2 (B)	60 meter wide with 30 meter green belt on both sides	Entire Route to have BRT
Sub-Arterial Roads			
X	V2 (C)	60 meter wide	
XI	V2 (D)	60 meter wide	Entire Route to have BRT
XII	V3	45 meter wide with 30 meter green belt on both sides	
XIII	V3 (A)	45 meter wide	

- (2) Width and alignment of other roads shall be as per sector plans or as per approved layout plans of colonies.
- (3) Benefit of only 50% of the area falling under major roads and adjoining green belts, if any, shall be allowed towards plotable area/FAR in the plotted/group housing colony while approving the layout plans for the sector/colony to be developed by Haryana Urban Development Authority and private colonizers. However, in respect of roads falling within the net planned area indicated in the sectoral plan, full FAR shall be allowed. In case of commercial colony and IT Park/Cyber City the benefit of 10% of FAR of the total area of the site or area falling under green belt and sector roads whichever is less shall be allowed.

IX. Facilities for Non-Motorized Traffic & Pedestrians:

While developing the Sectors and carrying out Development works, conscious efforts will be made to facilitate increasing use of non-motorized traffic and efforts will be made to create adequate spaces for pedestrians' movement also.

X. Non-conforming uses either existing or having valid Change of Land Use Permission:

- (1) With regard to the existing projects located in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue for a fixed period to be determined by the Director, but not exceeding ten years from the date of publication of Development Plan; provided that the owner of the building concerned:
 - (a) undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf;

- (b) during the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director; and
- (c) shall not be allowed to expand the existing project within the area of non conforming use.
- (2) With regard to the projects having valid Change of Land Use permissions and located in the zones other than conforming-use zone in the Development Plan, such non-conforming uses shall be allowed to continue, provided that the owner of the building concerned:
 - (a) undertakes to pay to the Director, as determined by him the proportionate charges towards the external development of the site as and when called upon by the Director to do so in this behalf; and
 - (b) during the interim period makes satisfactory arrangements for the discharge of effluent to the satisfaction of the Director.

XI. Discontinuance of non conforming uses:

- (1) If a non-conforming use of land has remained discontinued continuously for a period of two years or more, it shall be deemed to have been terminated and the land shall be allowed to be re-used or re-developed only according to the conforming use.
- (2) If a non-conforming use building is damaged to the extent of 50 percent or more of its re-production value by fire, flood, explosion, earthquake, war, riot or any other natural calamity, it shall be allowed to be re-developed only for a conforming use.
- (3) After the discontinuance of projects included under clause X, the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.
- (4) After a lapse of period fixed under clause X(1), the land shall be allowed to be redeveloped or used only for conforming use.

XII. Brick Kilns in Controlled Areas:

Siting of the brick kilns in the controlled areas shall be governed by the respective policy/guidelines issued by the competent authority from time to time.

XIII. Development to conform to sector plan and zoning plan:

Except as provided in regulation X, no land within major land use shall be allowed to be used and developed for building purposes unless the proposed use and development is according to the details indicated in the sector plan and zoning plan or the approved colony plan in which the land is situated.

XIV. Individual site to form part of approved layout or zoning plan:

No permission for erection or re-erection of building on a plot shall be given unless-

- (i) the plot forms a part of an approved colony or the plot is in such area for which relaxation has been granted as provided in regulation XVIII; and
- (ii) the plot is accessible through roads laid out and constructed upto the situation of the plot to the satisfaction of the Director.

XV. Area norms for various types of buildings/colonies:

- (1) The minimum size of the plots for various types of uses shall be as below:-

(i) Residential plot	50 Square metres
(ii) Residential plot in subsidized industrial housing or slum dwellers housing scheme(s) approved by the Government	35 Square metres
(iii) Shop-cum-residential plot	100 Square metres
(iv) Shopping booths including covered corridor or pavement in front	20 Square metres

(v) Local service industry plot	100 Square metres
(vi) Light industry plot	250 Square metres
(vii) Medium industry plot	8000 Square metres

(2) Area Norms for the development of colonies by the private developers shall be as under:

Type of colony	Area (in acres)
Residential Plotted Colony	Minimum 50 acres
Residential Group Housing Colony	Minimum 5 acres for independent group housing scheme or site forming part of the licenced colonies. However, in case a group housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of group housing site shall be as specified in the scheme.
Commercial Colony	Minimum 2 acres to maximum 4 acres
Industrial Colony	Minimum 25 acres

Note: The area under Licensed Group Housing Colony, otherwise specified, should not exceed 20% of the sector area.

XVI. Site coverage, Height and bulk of building under various types of buildings:

Site coverage and the height upto which building may be erected within independent residential and industrial plots, shall be according to the provisions contained in Chapter VII of the Rules. In the case of other categories, the maximum coverage and the floor area ratio, subject to architectural control, as may be imposed under regulation XVII shall be as under:-

Sr. No.	Type of Use	Maximum Ground Floor Coverage	Maximum Floor Area Ratio	Tier and Uses to be permitted in the Basement
1	Group Housing	35%	1.75	4 Level basement with the provision of parking and services shall be allowed if it satisfies the public health, fire and structural safety requirements.
2	Government Offices	25%	1.5	3 Level basement with the provision of parking and services shall be allowed if it satisfies the public health, fire and structural safety requirements.
3	Commercial:			
	(a) Integrated Corporate	40%	1.5-1.75 (As per zoning plan)	4 Level basement with the provision of parking and services shall be allowed if it satisfies the public health, fire and structural safety requirements.

	(b) Individual SCOs	100%	3.0	Single basement not exceeding 3 metres shall be permitted for storage, machine room of lifts, record, godowns and strong rooms and only ancillary to the permissible use of the site and for no other purposes.
	(c) Booths	100%	1.0	Single basement not exceeding 3 metres shall be permitted for storage.
4	Warehousing	60%	0.75	No basement shall be permitted

Note: Basement shall be permitted free of FAR. Storage material in the basement shall be in accordance with the provisions of National Building Code.

XVII. Building lines in front and rear of buildings:

These shall be provided in accordance with rules 51, 52 and 53 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965.

XVIII. Architectural Control:

Every building shall conform to architectural control prepared under rule 50 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965.

XIX. Relaxation of agriculture zone:

In the case of any land lying in Agriculture zone, Government may relax the provisions of this development plan:

- (a) for use and development of the land into a residential or industrial colony provided the coloniser has purchased the land for the said use and developed prior to the material date and the coloniser secures permission for this purpose as per Rules.
- (b) for use of land as an individual site (as distinct from an industrial colony)

Provided that-

- (i) the land was purchased prior to the material date;
- (ii) the Government is satisfied that the need of the industry is such that it cannot await alternative allotment in the proper zone;
- (iii) the owner of the land secures permission for building as required under the Rules;
- (iv) The owner of the land undertakes to pay to the Director, as determined by him, the proportionate charges as and when called upon by the Director in this behalf and during the interim period makes satisfactory arrangement for discharge of effluent.

Explanation: The word 'purchase' in the regulation shall mean acquisition of full proprietary rights and no lesser title, such as agreement to purchase etc.

- (c) The site should not fall within restricted belt notified under the 'Works of Defence Act, 1903' around Defence installations, if any.

XX. Density:

Every residential sector shall be developed to the sector density indicated as prescribed for it in the drawing subject to a maximum of 20 percent variation allowed on either side of the prescribed sector density.

XXI. Provision of farm house outside abadi-deh in agriculture zone:

Farmhouses shall be allowed only for bonafide use of landowner(s) provided he does not own a house in any urban area because the real object for allowing farmhouses in agriculture zone is to meet the housing needs of the farmers on a small portion of the farm so that he can take care of his agriculture produce while living on that farm. Hence, a farm house in agriculture zone, outside abadi-deh may be allowed if the area of the land is 2 acres or more on the following conditions:-

	Size of farm house	Main building of the dwelling unit	Ancillary building of main dwelling unit
(i) Site Coverage	2 acres minimum but CLU permission for the area falling under road reservation/proposed road widening as per Development Plan, shall not be considered. However the net area should not be less than 1.5 acres after excluding the area falling under the green belt/restricted belt and falling in Agriculture zone from applied area of 2 acres.	As applicable to residential plot equivalent to 250 square yards.	1 percent of the farm land (not more than 40% shall be used for labour/servant quarters)
	Upto 3 acres	As applicable to residential plot equivalent to 375 square yards.	-do-
	Upto 4 acres and above.	As applicable to residential plot equivalent to 500 square yards.	-do-
(ii) Height and Storey		11 metres, three Storeyed.	4 metres, single Storey.

(iii) Set back: It shall be at least 10 metres away from the edge of the agriculture land on all sides provided that if land attached to the farm house abuts a road, the house shall be constructed with a minimum set back from the edge of the road as under:-

- (a) Where the road is bye-pass to a scheduled road or an expressway. : 100 metres
- (b) Where the road is a scheduled road or as shown in the Development Plan : 30 metres
- (c) Any other road : 10 metres

(iv) Approach road Any revenue rasta/road defined in the revenue record.

(v) Basement Basement shall be permitted to the maximum extent of ground floor coverage but in the basement water closet and bathroom shall not be permitted.

(vi) Ledge, Loft and Mezzanine floor Ledge, Loft and Mezzanine floor shall be permitted within the building subject to the restrictions above as well as the restrictions stipulated in the definition given in Clause-II of these Zoning Regulations and Rules.

(vii) Services, water supply and drainage

(a) Good potable water supply should be available in the farm for human consumption incase farm house is built.

(b) Open sanitary drains or covered drains to be provided to clean the sheds in case of dairy farms, Drains are to be provided for carrying rain water in case of all buildings.

(c) Septic tank to be provided for disposal of human and animals waste as per provisions of the Rules.

(d) The distance between the septic and open well or tubewell shall be as provided in the Rules.

- (viii) The owner shall be permitted to construct boundary wall around the main dwelling unit and ancillary portion thereof and around remaining area of farm barbed wire fencing shall be allowed.
- (ix) The CLU permissions for setting up of farmhouse shall be considered in the area other than over exploited or critical areas as declared by Central Ground Water Board.

Provided that Government may amend the minimum size of the farm house for any schemes sponsored by the State Government/State agency for the proper utilization of the agriculture zone.

XXII. Provisions of Information Technology Units and Cyber Parks/Cyber Cities:

(ii) Location:

- (a) Information Technology Industrial Units will be located in Industrial Areas/Industrial Zones only;
- (b) Cyber Parks/Information Technology Parks will be located either in Industrial Areas or Industrial Zones abutting on sector roads in the form of integrated development. However, no manufacturing units will be permitted in such parks;
- (c) The location of Cyber Cities will be decided by the Government;

(iii) Size:

Serial Number	Type	Size
1	Information Technology Industrial Unit	1 to 5 acres
2	Cyber Park / Information Technology Park	5 to 15 acres
3.	Cyber City	minimum 50 acres

(iv) Miscellaneous:

I Parking:

- (a) One Equivalent Car Space for every 40 square meters of floor area shall be provided for parking in cyber park/Information Technology Park, Information Technology Industrial Unit and Cyber City;
- (b) Four tier basement for Information Technology Industry for meeting the requirement of parking shall be allowed subject to clearance from Public Health requirement.

II Other Activities:

- (a) Incidental commercial activities like Banks, Restaurants, Insurance Offices etc. shall be permitted subject to restriction of 4% of the total area of the Cyber Park/Information Technology Park;
- (b) Only 5% of the area of the Cyber City shall be allowed for Group Housing and 4% of the total area of the cyber city shall be permitted for Commercial/Institutional uses;
- (c) No residential plotted development shall be allowed in a Cyber City;
- (d) For a Cyber City Project if allowed in Agricultural Zone, the entrepreneur shall make the arrangement of water supply and other facilities like sewerage disposal/drainage etc;

III The Government may impose any other condition as deemed necessary from time to time.

XXIII Setting up of Communication Towers: Permission of Mobile Towers within the Controlled area shall be granted as per the policy dated 13th January, 2012 as amended from time to time;

XXIV Affordable Group Housing: The permission for affordable group housing projects within the Residential Zones of the Development Plans shall be granted as per the policy dated 19th August, 2013 as amended from time to time;

- XXV Safety against Seismic Hazards:** All the developments/building activities in the Development Plan area shall be carried out keeping in view the intensity of the seismic activity in development plan area, as per Seismic zone map of Indian Standard IS 1893. In order to take care of the same “the whole urban development shall be checked for safety against said intensity probability of occurrence, and upgraded for required seismic resistance in buildings and infrastructure as found necessary”.
- XXVI Provision of Zero Discharge in sectors/colonies:** Endeavor shall be made to develop all the sectors/colonies on zero discharge concept to encourage the use of recycled water.
- XXVII Relaxation of Development Plan:** Government may in case of hardship or with a view to save any structure constructed before the material date, relax any of the provisions of the Development Plan on principles of equity and justice on payment of such development charges and on such other conditions as it may deem fit to impose.

APPENDIX A
CLASSIFICATION OF LAND USES

Main Code	Sub Code	Main Group	Sub Group
100		Residential	Residential sector on neighborhood pattern
200		Commercial	
	210		Retail Trade
	220		Wholesale Trade
	230		Warehousing and Storage
	240		Office and Banks including Government office
	250		Restaurants, Hotels and Transient Boarding houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist house etc.
	260		Cinema and other places of public assembly on a commercial basis. Telephone exchanges.
	270		Professional establishments
300		Industrial	
	310		Service industry
	320		Light industry
	330		Extensive industry
	340		Heavy industry.
400		Transport and Communication	
	410		Railway yards, railway station and sidings.
	420		Roads, road transport depots and parking areas
	440		Airport/air stations
	450		Telephone Exchange etc.
	460		Broadcasting station
	470		Television station
	480		Logistic Parks/Zones/Dry Ports including Inland Container Depots and Warehouses
500		Public Utilities	
	510		Water Supply installation including treatment plants
	520		Drainage and Sanitary installation including Sewerage Treatment Plant and disposal works
	530		Electric power plants, substation etc.
	540		Gas Installation and gas work.
	550		Solid Waste Management sites
600		Public and Semi Public	
	610		Government Administrative Secretariat, District/Tehsil/Block Offices, Law Courts, Jails, Police Stations/Police Lines.

	620	Education, Cultural and Religious Institutions
	630	Medical and Health Institutions
	640	Cultural institution like Theatres, Opera Houses etc. of a predominantly non commercial nature
	650	Land belonging to defence
700	Open Spaces	
	710	Sports grounds, stadium and play grounds
	720	Parks
	730	Green belts, garden and other recreational uses.
	740	Cemeteries, crematories etc.
	750	Fuel filling stations and Bus queue shelters
	760	Water bodies/lakes/water recharge zones
	770	Mela Ground, Multipurpose ground
800	Agricultural land	
	810	Market garden, Orchards and Nurseries
	820	Land under agriculture operation, where no change of land use/license shall be granted.
	830	Land under staple crops
	840	Grazing and land pastures
	850	Forest land
	860	Marshy land
	870	Barren land
	880	Land under water
	890	Dairy farming
1000	Natural Conservation Zone	Agriculture, pisciculture, social forestry/ plantation including afforestation, regional recreational activities may be constructed with the permission of the Competent Authority over an area not exceeding 0.5% of the respective NCZ area in any case.

APPENDIX B

The permissible activities given under main land uses shall be allowed in accordance with the policy/parameters approved by the Government and at sites as approved by the Competent Authority in the Sector/Colony Plan.

I. Residential zone:

- (i) Residence
- (ii) Social community religious and recreational buildings
- (iii) Public utility buildings
- (iv) Educational buildings and all types of school and college where necessary.
- (v) Health institutions.
- (vi) Cinemas
- (vii) Commercial and professional offices.
- (viii) Retail shops, dhabas and restaurants.
- (ix) Local service industries.
- (x) Gas/Petrol filling stations.
- (xi) Bus stops, tonga, taxi, scooter and auto/rickshaw stand.

- (xii) Nurseries and green houses.
- (xiii) Any other minor needs ancillary to residential use
- (xiv) Starred hotels
- (xv) Clubs/Community Centres
- (xvi) Communication Towers
- (xvii) Guest/Boarding Houses
- (xviii) Any other use, which the Government may in public interest decide

II. Commercial zone

- (i) Retail Trade.
- (ii) Wholesale Trade.
- (iii) Warehouses and storages.
- (iv) Commercial offices and banks.
- (v) Restaurant and Transient Boarding Houses including public assistance institutions providing residential accommodation like Dharamshala, Tourist House etc.
- (vi) Cinemas, Hotels, Motels and other places of public assembly like theatres, club, Dramatic Club, etc. run on commercial basis.
- (vii) Professional establishments.
- (viii) Residences on the first and higher floors.
- (ix) Local service industry.
- (x) Public utility buildings.
- (xi) Gas/Petrol filling stations and service garages.
- (xii) Loading and unloading yards.
- (xiii) Parking spaces, bus stops, taxis, tonga, auto/rickshaw stand.
- (xiv) Town parks.
- (xv) Communication Towers
- (xvi) Any other use, which the Government may in public interest decide.

III. Industrial zone

- (i) Light industry
- (ii) Medium industry
- (iii) Obnoxious and Hazardous Industry
- (iv) Heavy industry
- (v) Service industry
- (vi) Warehouse and storages
- (vii) Parking, loading and unloading area
- (viii) Truck stand/bus stops, taxi, tonga and auto/rickshaw stand
- (ix) Public utility, community buildings, retail shops, banks, dhabas, restaurants, two/three/five star hotels and insurance offices subject to a maximum limit of 3 percent of the total area of the sector as under: -

Sr. No.	Name of Facility	Area		No. of facilities in a sector	Commercial component	Maximum Ground Coverage	Floor Area Ratio	Approach Road
		Minimum	Maximum					
1	Dhabas	500 sq. m	1000 sq. m	2	50 sq.m	40 %	0.40	Minimum 18 metres
2	Restaurants	1000 sq. m	2000 sq.m	2	10 %	30 %	1.50	Minimum 18 metres
3	Two/Three Star Hotels	1.0 Acre	2.5 Acres	2	15 %	30 %	As per commercial policy	Minimum 24 metres

4	Five Star Hotels	2.5 Acres	4.0 Acres	1	15 %	30 %	As per commercial policy	Sector Dividing Road with the provision of a service road
---	------------------	-----------	-----------	---	------	------	--------------------------	---

(x) Gas/Petrol filling stations and service garages.

(xi) Liquid Petroleum Gas godowns permitted by the Director.

(xii) Cyber Parks/Information Technology Parks/ Information Technology Industrial Units

(xiii) Health Facilities like Hospital, Dispensary, Nursing Home and Clinic as under:

Sr. No.	Name of facility	Area		No. of facilities in a sector	Residential component	Maximum ground coverage	Floor area ratio
		Minimum	Maximum				
1	Hospital	2.5 Acres	5.0 Acres	1	15 %	33 %	1.00
2	Dispensary	1.0 Acre	1.5 Acres	1	15 %	33 %	1.00
3	Nursing Home	250 sq. m	500 sq. m	2	Nil	60 %	1.00
4	Clinic	250 sq. m	500 sq. m	2	Nil	60 %	1.00

(xiv) Permissible Limits of Internal Land Use :-

The percentage of different land uses permissible in an Industrial colony shall be as under:-

Sr. No.	Category of Industrial Colony/ Park	Permissible Usage
1.	Upto 50 acres size	No changes proposed in the norms in this category- industrial – 45% (min.), residential/ housing use- 15% (max.), commercial- 5% (max).
2.	More than 50 acres upto 200 acres	Industrial – 40% (min.); residential/ housing use- 20% (max.) of affordable/ group housing/ plots; commercial- 5% (max.).
3.	More than 200 acres	Industrial – 35% (min.); mixed use- 30% consisting of residential/ housing - 25% (max.) comprising of affordable/ group housing/ plots; commercial- 5% (max.).

(xv) Communication Towers

(xvi) Ready mix concrete plant, wet mix plants, hot mix plants

(xvii) Weighing Bridge

(xviii) Service garage, Sale/Display centre -cum- Service Garage.

(xix) Any other use, which the Government may, in public interest decide.

IV. Transport and Communication Zone

(i) Railway yards, railway station and siding

(ii) Transport Nagar, Roads and Transport depots/Bus stands and parking areas

(iii) Airports and Air Stations

(iv) Telephone exchange

(v) Broadcasting stations

(vi) Television station

(vii) Agricultural, horticulture and nurseries at approved sites and places

(viii) Gas/Petrol filling stations and service garages

- (ix) Parking spaces ,bus stop-shelters, taxi, Tonga and auto/rickshaw stands
- (x) Logistics Hub/Container Yards, Inland Container Depot, Container Freight Station
- (xi) Warehouses up to a maximum limit of 5% of total area of the Sector
- (xii) Weighing Bridge.

V. Public Utilities

- (i) Water supply installations including treatment plants.
- (ii) Drainage and Sanitary installations including sewerage treatment plants and Disposal works.
- (iii) Electric Power plant and sub-station including grid sub-station.
- (iv) Gas installations and Gas works.
- (v) Solid Waste Management Sites.

VI. Public and semi public uses zone

- (i) Government offices ,Government Administration centers, secretariats and Police Station
- (ii) Educational, cultural and religious institutions
- (iii) Medical health institutions
- (iv) Civic/cultural and social institutions like theatres, opera houses etc. of predominantly non-commercial nature
- (v) Land belonging to Defence
- (vi) Dhabas, Restaurants as under: -

Sr. No.	Name of Facility	Area		No. of facilities in a sector	Commercial component	Maximum Ground Coverage	Floor Area Ratio
		Minimum	Maximum				
1	Dhabas	500 sq. mtrs	1000 sq. mtrs	2	50 sq. m	50 %	0.50
2	Restaurants	1000 sq. mtrs	2000 sq. mtrs	2	10 %	30 %	1.50

- (vii) Communication Towers
- (viii) Any other use, which the Government may in public interest decide

VII. Open spaces

- (i) Sports ground, stadium and play grounds
- (ii) Parks, green belts, garden and other recreational uses
- (iii) Cemeteries, crematories etc.
- (iv) Fuel filling stations, bus queue shelter along roads with the permission of Director
- (v) Public utility services like electric grid station, transmission lines, communication lines, water supply lines, sewerage lines, drainage lines in the green belts along the scheduled roads and major roads.
- (vi) Water bodies/lakes /water recharge zone.
- (vii) Communication Towers
- (viii) Mela Ground, Multipurpose ground
- (ix) Any other use, which the Government may in public interest decide.

VIII. Agriculture zone

- (i) Agricultural, Horticultural, dairy and poultry farming.
- (ii) Village houses within Abadi-deh
- (iii) Farm houses outside abadi-deh subject to restrictions as laid down in zoning regulation XXI
- (iv) Afforestation development of any of the part for recreation
- (v) Expansion of existing village contiguous to abadi-deh if undertaken as a project approved or sponsored by the Central Government or State Government.
- (vi) Milk chilling station and pasteurisation plant
- (vii) Bus Stand and railway station
- (viii) Air ports with necessary buildings
- (ix) Wireless stations
- (x) Grain godowns, storage space at sites approved by the Director
- (xi) Weather stations

- (xii) Land drainage and irrigation, hydroelectric works and tubewell for irrigation
- (xiii) Telephone and electric transmission lines and poles
- (xiv) Mining and extraction operations including lime and brick kilns, stones, quarries and crushing subject to the rules and at approved site
- (xv) Cremation and burial grounds
- (xvi) Gas/Petrol filling station and service garages
- (xvii) Renewable and non-renewable energy power plants.
- (xviii) Liquid Petroleum Gas storage godowns with the approval of the Director
- (xix) Non-polluting industrial units, otherwise specified, shall be permissible, provided that the site falls outside the restricted belt notified around defence installation under the 'Works of Defence Act, 1903' from time to time, subject to fulfillment of the following conditions:

Nature/Type of Industry	Rural Industries Scheme / Small Scale Industries.
Approach	(i) Located within half kilometer belt encircling the existing village Abadi-deh and approachable from public road/rasta other than scheduled road, National Highway and State Highway. (ii) On Public road/rasta (other than scheduled road, National Highway and State Highway) not less than 30 feet wide outside the half kilometer zone referred to in (i) above upto a depth of 100 metres along the approach road.
Area	Maximum 2 acres

- (xx) Dhabas, Restaurants, Motels, Resort and Amusement Park/ Theme Park along National Highway / Scheduled Roads in the area outside restricted/ green belt as under:-

Sr. No.	Permissible Activity	Area		Commercial Component	Maximum Ground Coverage	Floor Area Ratio
		Minimum	Maximum			
1	Dhabas	1000 sq. metres	1 acre	50 Sq.mtrs.	40%	0.4
2	Restaurant	2000 sq. metres	1 acre	15%	30%	1.5
3	Motel with banquet facilities	2.5 acres	5 acres	15%	30%	1.5
4	Resort	4 acres	10 acres	15%	30%	1.5
5	Amusement Park/Theme Park	2.5 acres	10 acres	15%	30%	0.5

Provided that the access permission is obtained from National Highway Authority of India if the site is located on National Highway, and from Executive Engineer, Public Works (Building and Roads) Department if the site is located on scheduled road.

(xxi) Banquet Hall:

Permissible Zone	Agriculture
Approach	1. Minimum width of the approach road must be 18 metres. 2. The access permission is required from XEN, PWD (B&R) if the site is located on scheduled road. 3. Approach from National Highways can be considered, if the site fulfills minimum distance norms from intersection/access and is located on minimum 7 meters wide service road or the applicant submits prior permission of access from NHAI.
Area Required	Minimum area :- 2.5 acres Maximum area :- 5.00 acres
FAR	0.5
Ground Coverage	30%

Conversion Charges	50% of the rates prescribed for commercial use
Permissible Ancillary uses within FAR	10% of the allowed FAR for Gift shop, STD Booth, Toy Centers and flowers shops etc.
Parking	Minimum 25% of the site area

(xxii) Microwave Towers/Stations, Seismic Centres and Telecommunication Centres

(xxiii) Communication Towers

(xxiv) Ready Mix Concrete Plants, Wet mix plants, Hot Mix Plants connected with the projects for which contract or work is assigned by Government or Government agency and to be set up on short term basis.

(xxv) Weighing Bridge

(xxvi) Any other use, which Government may in Public Interest, decide.

IX. Natural Conservation Zone:

(i) Agriculture and Horticulture.

(ii) Pisciculture.

(iii) Social Forestry / Plantations including afforestation.

(iv) Regional recreational activities after obtaining environmental clearance from Competent Authority.

X. Uses strictly prohibited:

Storages of petroleum and other inflammable material without proper license.

APPENDIX -1

Categories of Industries included in the scope / definition of Information Technology Industry

(A) Computing Devices including

Desktop

Personal Computer

Servers

Work-station

Nodes

Terminals

Network P.C.

Home P.C.

Lap-top Computers

Note Book Computers

Palm top Computer/PDA

(B) Network Controller Card/ Memories including

Network Interface Card (NIC)

Adaptor Ethernet /PCI/EISA/Combo/PCMICA

SIMMs Memory

DIMMs Memory

Central Processing Unit (CPU)

Controller SCSI/Array

Processors Processor/Processor Power Module/Upgrade

(C) Storage Units including

Hard Disk Drives/Hard Drives

RAID Devices and their Controllers

Floppy Disk Drives

- C.D. ROM Drives
- Tape Drives DLT Drives/DAT
- Optical Disk Drives
- Other Digital Storage Devices
- (D) Other**
 - Key Board
 - Monitor
 - Mouse
 - Multi-media Kits
- (E) Printers and Output Devices including**
 - Dot matrix
 - Laserjet
 - Inkjet
 - Deskjet
 - LED Printers
 - Line Printers
 - Plotters
 - Pass-book Printers
- (F) Networking products including**
 - Hubs
 - Routers
 - Switches
 - Concentrators
 - Trans-receivers
- (G) Software including**
 - Application Software
 - Operating system
 - Middleware/Firmware
- (H) Power supplies to Computer Systems including**
 - Switch Mode Power Supplies
 - Uninterrupted Power supplies
- (I) Networking/Cabling and related accessories**
(related to IT Industry)
 - Fibre Cable
 - Copper Cable
 - Cables
 - Connectors, Terminal Blocks
 - Jack Panels, Patch Cord
 - Mounting Cord/Wiring Blocks
 - Surface Mount Boxes
- (J) Consumables including**
 - C.D.ROM /Compact Disk
 - Floppy Disk
 - Tapes DAT/DLT
 - Ribbons
 - Toners

Inkjet Cartridges

Inks for Output devices

(K) Electronic Components

Printed Circuit Board/Populated PCB

Printed Circuit Board/PCB

Transistors

Integrated Circuits/ICs

Diodes/Thyristor/LED

Resistors

Capacitors

Switches(On/Off, Push button, Rocker, etc.)

Plugs/sockets/relays

Magnetic heads, Print heads

Connectors

Microphones/Speakers

Fuses

(L) Telecommunication Equipment including:

Telephones

Videophones

Fascimile machines/Fax cards

Tele-Printers/Telex machine

PABX/EPABX/ RAX/MAX Telephone Exchange

Multiplexers/Muxes

Modems

Telephone answering machines

Telecommunication Switching Apparatus

Anetna and Mast

Wireless datacom equipment

Receiving equipments like Pagers, mobile/Cellular Phones, etc.

VSATs

Video Conferencing Equipments

* Including Set Top Boxes for both Video and Digital Signaling.

(M) IT Enabled Services are business processes and services, the end products/services of which are:-

- Delivered outside India.
- Delivered over communication network., and
- Either externally contracted (out-sourced) or provided by a remote subsidiary of the same company (out-located).

Note: Services which would not be included are:-

- (i) Remote production/manufacturing units
- (ii) The Corporate offices of companies or their local branches
- (iii) Virtual business on Internet.

The following services which meet the above criteria would be included:-

- (i) Back-Office Operations
- (ii) Call Centers
- (iii) Content Development or Animation

- (iv) Data Processing
- (v) Engineering and Design
- (vi) Geographic Information System Services
- (vii) Human Resource Services
- (viii) Insurance Claim Processing
- (ix) Legal Database
- (x) Medical Transcription
- (xi) Payroll
- (xii) Remote Maintenance
- (xiii) Revenue Accounting
- (xiv) Supports Centres and
- (xv) Web-site Services.

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.

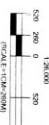
EXISTING LAND USE PLAN FOR CONTROLLED
AREA - V AROUND MUNICIPAL TOWN BAWAL

[illegible]

2. THIS EXISTING LAND USE PLAN HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF ACTUAL WORK AND SURVEY CONDUCTED BY MEMBERS OF CONSULTING ENGINEERS INDIA PVT. LTD. MUMBAI SEC. 29.



NAME & SENIORITY OF ALL THE GROUP MEMBERS

DRAWING: No. DTP (RE) 636/2013 DT. 16.12.2013/19.08.2014
C4-B-2015

CHEN, K. L. F. Y. *in situ* BAKED POLYMER

PLANNING ASSISTANT
- VERNICE KIMBLE

ASSIST TO OPEN PLASTER - SEE BRACKET VALVE

Ernst

10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116 10117 10118 10119 10120 10121 10122 10123 10124 10125 10126 10127 10128 10129 10130 10131 10132 10133 10134 10135 10136 10137 10138 10139 10140 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10147 10148 10149 10150 10151 10152 10153 10154 10155 10156 10157 10158 10159 10160 10161 10162 10163 10164 10165 10166 10167 10168 10169 10170 10171 10172 10173 10174 10175 10176 10177 10178 10179 10180 10181 10182 10183 10184 10185 10186 10187 10188 10189 10190 10191 10192 10193 10194 10195 10196 10197 10198 10199 10200 10201 10202 10203 10204 10205 10206 10207 10208 10209 10210 10211 10212 10213 10214 10215 10216 10217 10218 10219 10220 10221 10222 10223 10224 10225 10226 10227 10228 10229 10230 10231 10232 10233 10234 10235 10236 10237 10238 10239 10240 10241 10242 10243 10244 10245 10246 10247 10248 10249 10250 10251 10252 10253 10254 10255 10256 10257 10258 10259 10260 10261 10262 10263 10264 10265 10266 10267 10268 10269 10270 10271 10272 10273 10274 10275 10276 10277 10278 10279 10280 10281 10282 10283 10284 10285 10286 10287 10288 10289 10290 10291 10292 10293 10294 10295 10296 10297 10298 10299 10300 10301 10302 10303 10304 10305 10306 10307 10308 10309 10310 10311 10312 10313 10314 10315 10316 10317 10318 10319 10320 10321 10322 10323 10324 10325 10326 10327 10328 10329 10330 10331 10332 10333 10334 10335 10336 10337 10338 10339 10340 10341 10342 10343 10344 10345 10346 10347 10348 10349 10350 10351 10352 10353 10354 10355 10356 10357 10358 10359 10360 10361 10362 10363 10364 10365 10366 10367 10368 10369 10370 10371 10372 10373 10374 10375 10376 10377 10378 10379 10380 10381 10382 10383 10384 10385 10386 10387 10388 10389 10390 10391 10392 10393 10394 10395 10396 10397 10398 10399 10400 10401 10402 10403 10404 10405 10406 10407 10408 10409 10410 10411 10412 10413 10414 10415 10416 10417 10418 10419 10420 10421 10422 10423 10424 10425 10426 10427 10428 10429 10430 10431 10432 10433 10434 10435 10436 10437 10438 10439 10440 10441 10442 10443 10444 10445 10446 10447 10448 10449 10450 10451 10452 10453 10454 10455 10456 10457 10458 10459 10460 10461 10462 10463 10464 10465 10466 10467 10468 10469 10470 10471 10472 10473 10474 10475 10476 10477 10478 10479 10480 10481 10482 10483 10484 10485 10486 10487 10488 10489 10490 10491 10492 10493 10494 10495 10496 10497 10498 10499 10500 10501 10502 10503 10504 10505 10506 10507 10508 10
--

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CHIEF OF OPERATIONS PLANNING
ON BOARD/AT SEA/IN PORT

CHIEF
EXECUTIVE
TURNING & CONSULTING PLANNING & ENTRY

DEPTT OF T & C PLANNING HARYANA

